हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

● वर्ष-02 ● अंक- 56 ● भिलाई, बुधवार 16 सितम्बर 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

संक्षिप्त समाचार

करगिल युद्ध लड़ने वाले पूर्व वायुसेना अधिकारी पर गुरु ग्राम में हमला

गुरुग्राम। गुरुग्राम में भारतीय वायुसेना के एक सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन पर गंभीर हमले का मामला सामने आया है। कैप्टन की पहचान अमित कुमार गुप्ता के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि मैग्नम ग्लोबल पार्क में उन पर लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद गुप्ता पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक,रात गुप्ता अपने परिवार के साथ गोंजो रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे थे। परिवार को उतारने के बाद कार पार्क करने को लेकर उनका पार्किंग स्टाफ से विवाद हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें वैलेट, बेसमेंट और मल्टी-लेवल पार्किंग के बीच भटकाया गया। इसके बाद पार्किंग अटेंडेंट ने कथित तौर पर विंडशील्ड तोड़ने की भी कोशिश की। विवाद बढ़ने पर पार्किंग स्टाफ ने लोहे की रॉड से उन पर हमला कर दिया।

हिमालयी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे

नईदिल्ली। एक नए शोध में हिमालय को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसमें कहा गया है कि हिमालय एक खतरनाक सीमा के करीब पहुंच रहा है क्योंकि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, झीलें अस्थिर होती जा रही हैं और पहाड़ों की निगरानी नहीं हो पा रही है। हाल ही में नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालय की नाजुक स्थिति को लेकर ये नया आंकलन सामने आया है। सिस्टेमिक, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट के इस शोध में कहा गया है कि हिमालयी ग्लेशियर अब एक दशक पहले की तुलना में 65 प्रतिशत तेजी से अपना द्रव्यमान खो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लेशियरों के पीछे हटने से अस्थिर चट्टानों और झीलों का विस्तार हो सकता है। साथ ही, वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी से पर्माफ्रॉस्ट और ऊंचे पहाड़ी ढलोनों की अस्थिरता बढ़ रही है। शोध के अनुसार, हिमालयी जल भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 20 प्रतिशत आधार है, जो गेहूं, चावल, चाय, जलविद्युत और तीर्थयात्रा अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देता है।

बंगाल में तेज हुआ डेंगू का कहर, मरीजों का आंकड़ा 5,000 के पार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मानसून के मौसम के साथ ही डेंगू का प्रकोप विकराल रूप धारण करता जा रहा है। राज्य में इस वर्ष डेंगू संक्रमितों की कुल संख्या 5,000 के आंकड़े को पार कर गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे राज्य में 29 नगर पालिकाओं, 85 ब्लाकों और 278 ग्राम पंचायतों को डेंगू हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया है।स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, चिह्नित हॉटस्पॉट इलाकों में कर्मचारियों को अधिक गहन और रैंडम रक्त नमूना जांच के निर्देश दिए गए हैं।

पीएम आवास पर बहस के बाद पोस्टर वार

हमने नहीं बनाए तो जनता ने सजा दी-बघेल,झूठ बोलना बंद कीजिए-शर्मा

रायपुर। संवाददाता

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में मंगलवार को ऐतिहासिक घटना हुई। जब सूबे के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और वर्तमान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा के बीच पीएम आवास को लेकर सीधी बहस हुई। बहस का सार यह रहा कि, श्री बघेल ने स्वीकारा-हमने आवास नहीं बनाए इसलिए जनता ने हमें हराकर सजा दी। वहीं श्री शर्मा बार-बार यह कहते रहे कि, बघेल जी समझ सब रहे हैं, लेकिन समझाने की कोशिश कुछ और कर रहे हैं। श्री शर्मा बहस के बीच बार-बार श्री बघेल से झूठ मत बोलिए कहते रहे। वहीं श्री बघेल ने भी कहा-सरकार झूठ परोस रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने पीएम आवास योजना को लेकर राज्य सरकार के कामकाज का आंकड़ा सामने रखा। उन्होंने कहा कि साय सरकार के कार्यकाल में अब तक 11 लाख 75 हजार आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। उन्होंने दावा किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूरे देश में सबसे ज्यादा पीएम आवास छत्तीसगढ़ में बनाए गए। आवास निर्माण पर सरकार की ओर से करीब 16 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा अब 3 लाख 65 हजार नए मकानों के निर्माण की स्वीकृति भी मिल चुकी है। विजय शर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2020-21 में कोरोना काल के कारण

आवासों की स्वीकृति और निर्माण नहीं होने की बात कही जा रही है, लेकिन उनका दावा है कि देश के अन्य राज्यों में उस दौरान भी आवास स्वीकृत किए गए थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल का हवाला देकर पीएम आवास की स्वीकृति नहीं होने की बात कहना सही नहीं है। विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय गरीबों के आवास को लेकर गंभीर लापरवाही हुई थी। पीएम आवास के पोर्टल को लेकर भूपेश बघेल के बयान पर विजय शर्मा ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पोर्टल बंद होने की बात गलत है और इस संबंध में जनता के बीच गलतफहमी नहीं फैलानी चाहिए। विजय शर्मा ने कहा कि पोर्टल खुला हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय मुख्यमंत्री न्याय आवास योजना के पोर्टल पर पैसा डाला जा रहा था, जबकि पीएम आवास से संबंधित प्रक्रिया अलग थी। उन्होंने भूपेश बघेल के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को स्वीकृति, स्वीकार्यता और निर्माण के बीच का अंतर पता है। उनके मुताबिक इन अलग-अलग प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़कर आंकड़े पेश नहीं किए जाने चाहिए। विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल पीएम आवास को लेकर गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि पोर्टल बंद होने के कारण आवास स्वीकृत नहीं हुए।

कांग्रेस सरकार में केंद्र ने बंद कर दिया था पीएम आवास का पोर्टल : भूपेश बघेल

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम आवास को लेकर साय सरकार के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से 46 लाख मकान बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आंकड़ों को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। बघेल ने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय केंद्र सरकार की ओर से पीएम आवास का पोर्टल बंद कर दिया गया था। पोर्टल बंद होने के कारण उनकी सरकार के समय पीएम आवास की प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। इसके चलते लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला।

अगले 1-2 दिन में बाहर आ सकता है

कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को अंतरिम जमानत दी

नई दिल्ली। स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक कार्यकर्ता के पिता पर कथित हमले समेत अन्य आरोपों के संबंध में स्वतंत्र भारद्वाज को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत याचिका पर अपना आदेश 15 सितंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि आरोपी अगले 1-2 दिन में जेल से बाहर आ सकता है। भारद्वाज पर एक युवती के पिता संजय कुमार पर हमला

करने का आरोप लगाया गया है। एक पॉडकास्ट में स्वतंत्र ने स्वयं दावा किया था कि उसने डंडे से संजय पर हमला किया और उनका सिर फोड़ दिया। स्वतंत्र का यह भी कहना था कि संजय के सिर पर 60 टांके लगे थे।

कांस्टेबल भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ सरकार की एसएलपी खारिज,400+ अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ-कोर्ट

रायपुर। संवाददाता

छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती से जुड़े विवाद में लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद भर्ती की वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इससे 400 से अधिक उम्मीदवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कांस्टेबल भर्ती मामले में पूर्व में जारी आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही वेटिंग लिस्ट में मौजूद पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर बनी कानूनी अड़चन दूर हो गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजीव सचदेवा की

खंडपीठ ने की। अदालत ने संबंधित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब संबंधित विभाग को निर्धारित समय-सीमा में नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद वेटिंग लिस्ट में शामिल कई पात्र उम्मीदवार नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। मामला अदालत तक पहुंचने के कारण उनकी ज्वाइनिंग अटकी हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन अभ्यर्थियों की उम्मीदें फिर से मजबूत हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी सामने आने के बाद संबंधित अभ्यर्थियों में राहत और खुशी का माहौल है। 400 से अधिक उम्मीदवारों को अब नियुक्ति मिलने की उम्मीद है।

राजस्थान के नतीजों पर बोले पीएम मोदी

झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण-मोदी

नई दिल्ली/ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने के लिए वह राजस्थान की जनता के हृदय से आभारी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह जनादेश झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने एक बार फिर साफकर दिया है कि वह डबल इंजन सरकार की सुशासन और विकास की नीतियों के साथ खड़ी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता के इस समर्थन से राजस्थान को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने और लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का संकल्प और मजबूत होगा। उन्होंने राजस्थान निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले सभी बीजेपी प्रत्याशियों को बधाई दी। साथ ही पार्टी के समर्पित और मेहनती कार्यकर्ताओं का भी आभार जताते हुए उन्हें जीत की बधाई दी। राजस्थान नगर निकाय चुनाव में अब तक घोषित 10,210 वार्डों के नतीजों में बीजेपी ने 4,171 वार्डों पर और कांग्रेस ने 3,597 वार्डों पर जीत हासिल की है। पार्टी की इस सफलता को गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थानी में संदेश लिखते हुए कहा, 'घणी-घणी बधाइयां राजस्थान।

1980 से 'गायब' है कालीघाट मंदिर के बैंक वॉल्ट की चाबी

कोलकाता। महानगर कोलकाता के आध्यात्मिक, ऐतिहासिक एवं 51 शक्तिपीठों में से एक कालीघाट मंदिर दुनिया भर में आस्था का केन्द्र है। हर जगह से मायूस श्रद्धालु महामाया काली के दरबार में आते हैं। लेकिन मंदिर के प्रबंधन, वित्तीय धांधली और संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक व कानूनी बवंडर खड़ा हो गया है। मंदिर के संरक्षक रहे सवर्ण रॉयचौधरी परिवार ने मंदिर ट्रस्ट में व्यापक भ्रष्टाचार और निरंकुशता का आरोप लगाते हुए देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सवर्ण रॉयचौधरी परिवार परिषद के सचिव देबर्षि रॉयचौधरी ने देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत को एक औपचारिक पत्र भेजा।

सुप्रीम कोर्ट बोले-जनता का भरोसा जीते

मजबूत लोकतंत्र के लिए आलोचना बहुत जरूरी...

नई दिल्ली/ एजेंसी

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को जोर देकर कहा कि न्यायपालिका कभी भी खुद को जांच के दायरे से बाहर रखकर जनता का भरोसा नहीं जीत सकती। न्यायतंत्र को जांच, सवाल और आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने यह बयान दिवंगत पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता रामजेठ मालानी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दिया। नई दिल्ली में जस्टिस सीन टू बी डन: ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक ट्रस्ट एज पिलर्स ऑफ द लीगल

सिस्टम पर छठा राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर देते हुए, जस्टिस कांत ने इस बात पर जोर दिया कि संस्थागत जवाबदेही और आत्म-सुधार के लिए अदालती कामकाज की निष्पक्ष, जानकारी वाली और रचनात्मक आलोचना जरूरी है। सीजेआई सूर्यकांत ने एनसीई आरटी की एक पाठ्यपुस्तक के बारे में सुप्रीम कोर्ट की हालिया सू मोटो कार्यवाही का जिक्र करते हुए कहा कि एक संस्था के तौर पर न्यायपालिका की आलोचना के खिलाफ नहीं है, और न ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि न्यायिक कार्य की निष्पक्ष, जानकारी वाली और रचनात्मक आलोचना एक मजबूत संवैधानिक लोकतांत्र की वैध और जरूरी खासियत है। सीजेआई ने आगे कहा कि यह पारदर्शिता का हृदय है, क्योंकि कोई भी अदालत खुद को जांच से परे रखकर जनता का भरोसा नहीं जीत सकता है।

बांग्लादेश में बड़ा फैसला

हिंसा मामले में अवामी लीग के 7 नेताओं को मौत की सजा

ढांका/ एजेंसी

बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल 2 ने प्रतिबंधित अवामी लीग के 7 वरिष्ठ नेताओं को मौत की सजा सुनाई है। यह फैसला वर्ष 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने और मानवता के खिलाफअपराधों के मामले में सुनाया गया है। न्यायमूर्ति नजरुल इस्लाम चौधरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सातों आरोपियों की गैरमौजूदगी में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी नेताओं की 50 प्रतिशत संपत्ति जब्त कर हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण 2 ने अवामी लीग के सात शीर्ष नेताओं को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया है। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नजरुल इस्लाम चौधरी, न्यायमूर्ति मंजुरुल बशिद और न्यायमूर्ति शाहरीयार कबीर की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत में सातों आरोपियों की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया तथा उनके बचाव के लिए सरकारी वकील मौजूद थे। फांसी की सजा पाने वालों में अवामी लीग के महासचिव ओबैदुल कादेर, बहाउद्दीन नसीम और पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद अली अराफात शामिल हैं। इसके अलावा जुबो लीग अध्यक्ष शेख फजले शम्स परश और महासचिव मैनुल हुसैन खान निखिल को भी मृत्युदंड दिया गया है। साथ ही छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग के अध्यक्ष साद्दाम हुसैन और महासचिव शेख वली आसिफ एनान को सजा हुई है। अदालत ने दोषी नेताओं की

50 प्रतिशत संपत्ति जब्त कर 'जुलाई फाउंडेशन' के जरिए पीड़ितों में बांटने का निर्देश दिया है। यह मुआवजा 2024 के हिंसक प्रदर्शनों में मारे गए निर्दोष लोगों के परिजनों और घायलों को सहायता के रूप में दिया जाएगा। अदालत ने माना कि आरोपियों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर हिंसा भड़काने और हत्याओं की साजिश में मुख्य भूमिका निभाई थी। यह मामला जुलाई और अगस्त 2024 में हुए छात्र नेतृत्व वाले विशाल प्रदर्शनों से जुड़ा है जिन्हें 'जुलाई विद्रोह' कहा जाता है। शुरुआत में यह आंदोलन नौकरियों में कोटा व्यवस्था के खिलाफथा, जो बाद में सरकार के खिलाफ जनविद्रोह में बदल गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार 15 जुलाई से 5 अगस्त 2024 के बीच हुई हिंसा में लगभग 1,400 लोगों की जान गई। इस जनविद्रोह के चलते 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार सत्ता से बाहर हो गई और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आ गईं। नवंबर 2025 में इसी ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को भी गैरमौजूदगी में फांसी की सजा सुनाई थी। हसीना को 'सुपीरियर कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी' के तहत दोषी ठहराया गया था, जबकि उन्होंने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का दावा किया है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 2024 में शुरू हुआ छात्र आंदोलन पहले सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ था। बाद में यह आंदोलन शेख हसीना सरकार के खिलाफबड़े जनविद्रोह में बदल गया। जुलाई और अगस्त में देशभर में प्रदर्शन हुए। सरकार ने इन्हें दबाने की कोशिश की। 5 अगस्त 2024 को हसीना सरकार गिर गई और वे भारत चली गईं। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि ओबैदुल कादर ने पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के निर्देश दिए। एक फॉरेंसिक जांच वाले ऑडियो में उन्हें छात्र लीग के नेताओं से बात करते हुए सुना गया था। आरोप है कि उन्होंने मीडिया पर नियंत्रण रखने और खबरें दबाने में भी भूमिका निभाई। अराफात पर मीडिया नियंत्रण का आरोप लगाया गया था, जबकि नसीम पर पार्टी की प्रतिक्रिया संगठित करने का आरोप था। यह फैसला पहले आए फैसले के बाद आया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बेमेतरा जिले को दी 183 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

30 कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन, शिक्षक सम्मान समारोह में 81 सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं 42 प्रतिभावान विद्यार्थियों का हुआ सम्मान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बेमेतरा के स्कूल ग्राउंड मैदान में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह एवं लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने बेमेतरा जिलेवासियों को 183.36 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 30 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें 22 कार्यों का भूमिपूजन 153.55 करोड़ रुपये की लागत से तथा 08 कार्यों का लोकार्पण 29.80 करोड़ रुपये की लागत से किया गया। इस अवसर पर बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू के मांग पर मुख्यमंत्री विष्णु सायं ने गौरव पथ के लिए दो करोड़ रुपए एवं तिरैया में सब स्टेशन खोलने की घोषणा किए गए । विभागवार कार्यों की बात करें तो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 05 कार्यों के लिए 131.82 करोड़ रुपये की लागत से भूमिपूजन किया गया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत 07 कार्यों की लागत 14.17 करोड़ रुपये है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संबंधित 01 कार्य के लिए 2.76 करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 01 कार्य के लिए 2.54 करोड़ रुपये की लागत से भूमिपूजन किया गया। इसी तरह जनपद पंचायत बेरला के अंतर्गत 05 कार्यों के लिए 1.42 करोड़ रुपये की लागत से भूमिपूजन किया गया। जनपद पंचायत बेमेतरा के अंतर्गत कुल 05 कार्यों में 03 कार्यों का भूमिपूजन 82.88 लाख रुपये तथा 02 कार्यों का लोकार्पण 48.40 लाख रुपये की लागत से किया गया, जिनकी कुल लागत 1.31 करोड़ रुपये है। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत 02 कार्यों का 2.31 करोड़ रुपये की लागत से तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत 01 कार्य का 25 लाख रुपये की लागत से लोकार्पण किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, पुलिस अधोसंरचना एवं ग्रामीण विकास से जुड़े इन विकास कार्यों की सौगात से बेमेतरा जिले में विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। इन कार्यों से जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी तथा विकास की दिशा में नए अवसर उपलब्ध होंगे।

81 सेवानिवृत्त शिक्षकों का हुआ सम्मान

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा जिले के 81 सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। इसके साथ ही जिले के प्रतिभावान 42 विद्यार्थियों को बेमेतरा के दानदाताओं के माध्यम से सम्मानित किया गया। शिक्षक सम्मान समारोह के आयोजन का बेमेतरा में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। वर्ष 1986 में तत्कालीन विधायक बेमेतरा स्वर्गीय रेवेन्द्र सिंह वर्मा ने नागरिकों एवं अधिकारियों के सहयोग से इस शिक्षक सम्मान समारोह की शुरुआत की थी। तब से यह सम्मान समारोह लगातार 40 वर्षों से अनवरत आयोजित होता आ रहा है। इस आयोजन के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के साथ-साथ जिले की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाता है।

ट्राइसिकल मिलने पर दिव्यांग तनुश्री ने कलेक्टर एवं पार्षदो का धन्यवाद दिया

दल्लीराजहरा। नगर पंचायत चिखलाकसा के वार्ड क्रमांक 13 निवासी 16 वर्षीय दिव्यांग बालिका तनुश्री, पिता नेम सिंह की मदद के लिए भाजपा पार्षद ताराचंद पाथोड़ें एवं शान्तनु मेश्राम ने कलेक्टर बालोद को पत्र लिखकर बैटरी चलित ट्राइसिकल उपलब्ध कराने की मांग की थी। कलेक्टर को दिए पत्र में पार्षदों ने बताया था कि तनुश्री शारीरिक रूप से लगभग 75 प्रतिशत दिव्यांग है। दिव्यांगता के कारण उसे आने-जाने में काफी परेशानी होती है और वह स्वयं कहीं आने-जाने में असमर्थ है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसके माता-पिता अपने खर्च से बैटरी चलित ट्राइसिकल खरीद पाने में सक्षम नहीं हैं। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण बालिका शिक्षा से भी वंचित हो रही है। ऐसे में पार्षदों ने कलेक्टर से बालिका और उसके परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए मानवीय आधार पर बैटरी चालित ट्राइसिकल उपलब्ध कराने का आग्रह किया था।पार्षदों ने उम्मीद जताई थी कि प्रशासन की मदद से तनुश्री को आवागमन में सुविधा मिलेगी और वह अपनी शिक्षा एवं दैनिक गतिविधियों को अधिक स्वतंत्रता के साथ जारी रख सकेगी। जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने ट्राइसिकल आबंटित करने का आदेश जारी किया । ट्राइसिकल मिलने पर तनुश्री ने दिल से कलेक्टर एवं पार्षदो का धन्यवाद दिया। पार्षद ताराचंद पाथोडे एवं शान्तनु मेश्राम ने भी त्वरित कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

राज्यपाल रमेन डेका ने 'द प्राइम जिम' का किया भव्य शुभारंभ

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने आज बेमेतरा शहर के परशुराम चौक स्थित अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित द प्राइम जिम का फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने जिम का अवलोकन किया और संचालकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा कि आज के समय में शारीरिक फिटनेस अत्यंत आवश्यक है। युवा नशे से दूर रहकर जिम और खेलों से जुड़ेंगे तो शरीर के साथ-साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ युवा ही स्वस्थ छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का निर्माण करेंगे। जिम के शिवम् तिवारी द्वारा बताया गया कि इस जिम में युवाओं एवं महिलाओं के लिए आधुनिक कार्डियो, वेट ट्रेनिंग मशीनें, पर्सनल ट्रेनिंग एवं डाइट काउंसलिंग की विशेष सुविधा उपलब्ध है। इस गरिमामय अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारी, नगर के गणमान्य नागरिक, खेल प्रेमी एवं बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे।

सहकारी बैंक की शाखाओं एवं समितियों में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का आयोजन

बेमेतरा। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुख्यालय सभा भवन में सहकारी जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारियों की बैठक प्रीतपाल बेलचंदन अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.दुर्ग द्वारा ली गई जिसमें 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाये जाने की जानकारी दी गयी। उक्त कार्यक्रम दिनांक 17.09.2026 को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ''सहकारिता के दीप'' जलाकर मनाया जाना है। उक्त दिवस में बैंक कार्यक्षेत्र अंतर्गत प्रधान कार्यालय दुर्ग, नोडल कार्यालय जिला बालोद/बेमेतरा जिला दुर्ग, बालोद, बेमेतरा अंतर्गत 73 शाखाओं के साथ सभी प्राथमिक कृषि/विपणन/बुनकर/औद्योगिक/मत्स्य/उपभोक्ता एवं अन्य सहकारी समितियों में 101 दीप का प्रज्जवलन सायं 7 बजे बैंक/समिति कार्यालय में समिति के अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। उक्त कार्यक्रम में समिति के कार्यक्षेत्र के कृषक सदस्यों को सादर आमंत्रित कर तिलक लगाकर स्वागत करना है। बैठक में नरेष यदु, उपाध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.दुर्ग, मुकेष ध्रुव संयुक्त आयुक्त सहकारिता दुर्ग संभाग, लखनलाल गुरुपंच, पूर्व संचालक, एस.के.वर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संजीव तिवारी, प्रदेष संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ, जयनारायण बस्तरिया संभाग संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ, यषवंत कुमार वर्मा सहकारिता प्रकोष्ठ धमधा, राजेन्द्र यादव महामंत्री किसान मोर्चा जिला दुर्ग, मुकेष बेलचंदन, प्रदेष भाजपा किसान मोर्चा कार्यसमिति सदस्य, कुलदीप साहू प्राधिकृत समिति परसदा, तुलेष्वर चन्द्राकर प्राधिकृत गोरकापार, शीतल कुमार चन्द्राकर, वरिष्ठ किसान अषोक कुमार (पप्पु यादव) जिला संयोजक सहकारिता, तिलक राम निषाद मिडिया प्रभारी सहकारी प्रकोष्ठ जिला बालोद, श्यामलाल साहू, संयोजक सहकारी प्रकोष्ठ दुर्ग, सुरेन्द्र देषमुख जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा बालोद, बैंक अधिकारी हृदेष शर्मा, एस.के.निवसरकर, सु कुसुम ठाकुर, आर.के. वारे, नोडल अधिकारी बेमेतरा, होमंत पटेल सहायक नोडल बालोद उपस्थित रहें।

कृषि व्यापारी संघ की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा

बेमेतरा। कृषि व्यापारी संघ की त्रैमासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में कृषि व्यापार में अव्यवहारिक मापदंडों के पालन में आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। तथा इसके निराकरण हेतु उप संचालक कृषि को ज्ञापन सौंप कर चर्चा कर हल निकालने का प्रयास किए जाने का निर्णय लिया गया जिसमें प्रमुख रूप से कंप्यूटरीकृत स्टॉक संधारण विकल्प को अनुमति प्रदान करना, स्त्रोत प्रमाण पत्र जोड़ने की प्रक्रिया को सरलीकृत करना तथा कुछ अव्यावहारिक नियमों को शिथिल करने की बात रखी जाएगी।साथ ही कृषि व्यापार नियमों के पालन हेतु सभी पंजीकृत व्यापारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का भी अनुरोध किया जाएगा। व्यापारियों ने पुनः विभागीय नियमों के अनुरूप कार्य करने तथा अमानक और प्रतिबंधित सामग्रियों का विक्रय न करने के संकल्प को दोहराया साथ ही ,गाँव गांव घूम कर सस्ते की आड़ में अमानक सामग्रियों का विक्रय करने वालों से सावचेत करने संघ के माध्यम से अभियान चलाकर किसानो में जनजागरण करने का निर्णय लिया गया।साथ ही विभाग से ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर एवं दंडात्मक कार्यवाही करने की अपील की गई।इसके लिए संघ सक्रिय रहेगा। संगठन को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से इसका पुनर्गठन और विस्तार किए जाने का निर्णय किया गया है।सर्वप्रथम इस साल दिसंबर तक सभी कृषि व्यापारियों को संगठन से जोड़ने अभियान चलाया जाना है।और मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने का निर्णय लिया गया।इसके बाद जनवरी 2027 में पुनर्गठन तथा सभी की सक्रिय सहभागिता,दायित्वों के निर्धारण हेतु चुनाव का आयोजन किया जाएगा।इसमें केवल पंजीकृत कृषि व्यापारी ही भाग ले सकेंगे। बैठक में मुख्य रूप से संघ के अध्यक्ष सिद्दीक खान संरक्षक ओमप्रकाश राठी ,समीर टिकरिहा, युवराज पटेल, अश्वनी बंजारे,संतोष माहेश्वरी, मिथिलेश साहू, शैलेश माहेश्वरी, प्रशांत वर्मा,राजेश गांधी,कमल नारायण अग्रवाल सुरेश वैष्णव युवा राज पटेल,सहित बड़ी संख्या के व्यापारी उपस्थित थे ।

आशीष छाबड़ा ने कोटवारी भूमि को लेकर सौंपा राज्यपाल को ज्ञापन

बेमेतरा। बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने सर्किट हाउस में पधारे हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात करते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा जिसमें बेमेतरा जिला मुख्यालय के पटवारी हल्का नंबर 27 कोबिया स्थित कोटवारी/ सेवा भूमि के विक्रय किए जाने का मामला राज्यपाल के संज्ञान में लाया सौंपे गए ज्ञापन में पूर्व विधायक ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से शिकायत करते हुए कहा है कि पूर्व में जो कोटवारी भूमि संतू दास मानिकपुरी के नाम पर दर्ज रही है उसका नामांतरण/फौती उसके पोते प्रदीप कुमार मानिकपुरी के नाम पर कर दिया गया है जबकि कोटवारी भूमि का फौती दर्ज नहीं किया जाता ऐसे में उसे भूमि को विक्रय करने के नाम से यह कार्य किया गया हैंजिसमें जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने मांग की है कि कोबिया सहित अन्य ग्रामो की भी कोटवारी भूमि जिन्हें सेवा भूमि कहा जाता है का अवैध रूप से विक्रय किए जाने एवं रजिस्ट्री किए जाने के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है जिसकी जांच की जाए तथा संबंधित दोषियों पटवारी पर कार्यवाही की जाए पूर्व विधायक ने बताया कि ग्राम कोबिया जो अब वर्तमान में बेमेतरा नगर पालिका का वार्ड हो चुका है जहां कोटवार नियुक्त करने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है वहां पर पूर्व में कोटवार को दी गई सेवा भूमि को विक्रय कर दिया गया है इसमें तत्कालीन राजस्व विभाग के अधिकारियों की भी भूमिका संदिग्ध रही है जिसकी जांच किया जाना आवश्यक है और यह शिकायत एकमात्र कोबिया कि नहीं है बल्कि अन्य जगहों से भी इसी तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही है इसलिए आवश्यक है कि इसकी जांच की जाए और दोषियों को दंड दिया जाए।

जिला के विभिन्न क्षेत्रों के चौक चौराहों पर गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापना शुभ मुहूर्त में किया गया

बेमेतरा। देवो के देव महादेव की पुत्र भगवान श्रीगणेश जी चतुर्थी पर्व पर श्रद्धालुओं ने भारी उत्साह श्रद्धा भक्ति के साथ जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह विभिन्न चौक चौराहों के पंडाल में लंबोदर महाराज की छोटे से लेकर बड़ी बड़ी मूर्ति की स्थापना विभिन्न शुभ मुहूर्त में स्थापित किया गया इस के पूर्व शहर के मुख्य चौक-चौराहों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार व रविवार से ही लोग अपने गांव घरों के लिए प्रतिमा ले जाते हुए नजर आए। विघ्नहर्ता भगवान गणेश प्रथम पूजनीय देवता है। मान्यता है कि भगवान गणेश की उपासना करने से सुख-समृद्धि, बुद्धि व बल आदि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गणपति बप्पा को लोग ढोल-नगाड़ों के साथ ही सेवा गीत और उन्हें स्थापित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना किया। वहीं लगातार 10 दिनों तक पूजा अर्चना के साथ भक्तगण सेवा करेंगे। उसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें विदा किया जाएगा। गणेश चतुर्थी को लेकर शहर के चौक-चौराहों और गली-मोहल्लों से लेकर ग्रामीण अंचलों में तैयारियां पूरी कर ली गई थी कई घरों में बच्चों के द्वारा गणपति बप्पा की मूर्ति श्रद्धा भक्ति के स्थापना किया गया है । गणेशोत्सव के लिए समितियों ने आकर्षक और भव्य पंडाल बना कर तैयारी कर गणेश स्थापना किया गया ग्रामीण अंचल में अलग-अलग आकर में भगवान गणेश की प्रतिमाएं विराजमान किया गया है। शहर मुख्यालय में दर्जनों स्थानों पर धूमधाम से विघ्नहर्ता की स्थापना हुई इसके अलावा भक्तिमय कार्यक्रमों का भी आयोजन में छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त विभिन्न कलाकारों का बुलाया गया है। शहर के गश्ती चौक, बाजार पारा, नयापारा, दुर्ग रोड, प्रताप चौक, बस स्टैंड सहित कोलेबिया मोहभट्टा पिकरी सिंघोरी सहित अन्य स्थलों पर गणपति बप्पा की मूर्ति को स्थापित किया गया है।

कर्मचारी-अधिकारी प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ में महेश्वर साहू प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त

दल्लीराजहरा। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू, अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक बी. सी. साहू, व प्रदेश महामंत्री शंकर साहू की अनुशंसा पर संगठनात्मक विस्तार करते हुए कर्मचारी - अधिकारी प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ में महेश्वर साहू को प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी महेश्वर साहू पूर्व से ही समाज के विकास, शिक्षा और सामाजिक उत्थान के कार्यों में सक्रिय रूप से अपना योगदान देते रहे हैं। महेश्वर साहू प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी ने इस महत्वपूर्ण नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के अधिकारी-कर्मचारी प्रकोष्ठ द्वारा मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया गया है मैं पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ उसका निर्वहन करूंगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के मार्गदर्शन में कर्मचारी अधिकारी-प्रकोष्ठ सशक्त होगा और शिक्षा तथा जनसेवा के कार्यों में निरंतर प्रगति करेगा। महेश्वर साहू को कर्मचारी अधिकारी प्रकोष्ठ के प्रदेश सोशल मिडिया प्रभारी का दायित्व मिलने पर बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित करने वालों में प्रमुख रूप से राजकुमार साहू ,प्रेम प्रकाश साहू, धर्मेन्द्र साहू, उत्तम साहू,बोधन साहू, मनोज साहू, सुभाष साहू ,हरि सौंदर्य साहू, मगेश्वर साहू, तरुण गंजीर, प्यारेलाल साहू , राजेश साहू आदि प्रमुख रूप से शामिल है।

एक साल में अधिकारी संलग्न, दो साल से साहू प्रभार में, प्रशासनिक फैसलों का अलग पैमाना

कवर्धा। जनपद पंचायत बोड़ला के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह को जिला पंचायत कबीरधाम में संलग्न किए चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक गलियारों से लेकर क्षेत्र तक इस फेरबदल की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। करीब एक वर्ष तक बोड़ला जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विकासखंड की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी को अचानक जिला पंचायत में संलग्न किए जाने के पीछे आखिर प्रशासनिक जरूरत क्या थी, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। आदेश में संलग्नीकरण का कारण स्पष्ट नहीं होने से चर्चाओं को और हवा मिल रही है। बोड़ला जनपद क्षेत्र उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा के विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ऐसे में यहां होने वाले महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलावों पर क्षेत्र की नजर स्वाभाविक रूप से बनी रहती है। हालांकि आकाश सिंह के संलग्नीकरण को उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा से जोड़ने का कोई आधिकारिक आधार सामने नहीं आया है। इसलिए इससे जुड़ी चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

आकाश सिंह ने करीब एक वर्ष तक बोड़ला जनपद पंचायत में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान पंचायतों के कामकाज, विकास योजनाओं की निगरानी और स्थानीय प्रशासनिक परिस्थितियों से वे परिचित हुए। पंचायत स्तर पर समन्वय और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी उनके कार्यकाल की चर्चा होती रही। ऐसे में संलग्नीकरण के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक अधिकारी ने करीब एक साल में क्षेत्र की पंचायत व्यवस्था, स्थानीय परिस्थितियों और विकास कार्यों को समझ लिया था, तब अचानक उनकी जिम्मेदारी बदलने की प्रशासनिक आवश्यकता क्यों पड़ी।

बोड़ला की व्यवस्था को लेकर सवाल इसलिए और गंभीर हो जाते हैं क्योंकि जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड में विकास अधिकारी शिव कुमार साहू करीब दो वर्षों से पदस्थ हैं और उन्हें जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का प्रभार भी सौंपा गया है। एक तरफ बोड़ला में करीब एक वर्ष तक जिम्मेदारी संभालने वाले प्रभारी सीईओ को जिला पंचायत में संलग्न कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर सहसपुर लोहारा में करीब दो वर्षों से विकास अधिकारी को ही जनपद सीईओ का प्रभार देकर व्यवस्था चलाई जा रही है।

प्रभार व्यवस्था जरूरत के समय प्रशासनिक विकल्प हो सकती है, लेकिन जब यही व्यवस्था वर्षों तक चलती है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि नियमित पदस्थापना और अतिरिक्त प्रभार के लिए प्रशासनिक कसौटी क्या है।जिले की प्रशासनिक व्यवस्था में एक और मामला चर्चा में है। सहायक प्रोग्रामर दिलीप साहू को कार्यक्रम अधिकारी यानी पीओ का प्रभार दिया गया है, जबकि कार्यक्रम अधिकारी सेव चंद्रवंशी को जिला पंचायत में संलग्न किया गया है। इस व्यवस्था ने जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। जिस अधिकारी के पास नियमित रूप से कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारी थी, उसे जिला पंचायत में संलग्न किया गया और उसके स्थान पर सहायक प्रोग्रामर को पीओ का प्रभार दे दिया गया। एक ओर अधिकारी को उसके कार्यक्षेत्र से हटाकर संलग्न किया जा रहा है, दूसरी ओर दूसरे अधिकारी (कम योग्यता)को अतिरिक्त जिम्मेदारी देकर व्यवस्था चलाई जा रही है। यही विरोधाभास अब प्रशासनिक व्यवस्था की एकरूपता पर सवाल खड़े कर रहा है।

प्रशासनिक व्यवस्था के शिकार कितने अधिकारी

जिले में यह सवाल भी उठ रहा है कि ऐसे कितने अधिकारी और कर्मचारी होंगे, जो लंबे समय से प्रभार, संलग्नीकरण अथवा अस्थायी व्यवस्था के बीच काम कर रहे होंगे। कहीं वर्षों से अतिरिक्त प्रभार जारी है, तो कहीं जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारी को अचानक दूसरी जगह संलग्न कर दिया जाता है। प्रभार व्यवस्था का उद्देश्य यदि केवल अस्थायी प्रशासनिक आवश्यकता पूरी करना है तो उसका लंबे समय तक जारी रहना भी समीक्षा का विषय होना चाहिए। वहीं बार-बार जिम्मेदारी बदलने से योजनाओं की निगरानी और विकास कार्यों की निरंतरता प्रभावित होने की आशंका रहती है।

बोड़ला में नई व्यवस्था, नई चुनौती

कलेक्टर कबीरधाम के आदेश के अनुसार आकाश सिंह को आगामी आदेश तक जिला पंचायत में कार्य करने के लिए संलग्न किया गया है। उनके स्थान पर जिला पंचायत में प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी के रूप में कार्यरत योगेश वर्मा को जनपद पंचायत बोड़ला के सीईओ का अस्थायी रूप से समस्त प्रभार सौंपा गया है। अब योगेश वर्मा के सामने बोड़ला की पंचायत व्यवस्था, लंबित विकास कार्यों और शासन की योजनाओं में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने की चुनौती होगी। दूसरी ओर जिला पंचायत में आकाश सिंह के अनुभव का उपयोग किस जिम्मेदारी में किया जाता है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।

फैसला प्रशासन का, नजर जनता की

प्रशासनिक फेरबदल शासन की सामान्य प्रक्रिया है। कार्यहित और प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। लेकिन जब एक अधिकारी को करीब एक वर्ष बाद संलग्न किया जाता है, दूसरे विकासखंड में करीब दो वर्षों से अतिरिक्त प्रभार चलता है और कार्यक्रम अधिकारी को जिला पंचायत भेजकर सहायक प्रोग्रामर को पीओ का प्रभार दिया जाता है, तो मामला केवल एक आदेश तक सीमित नहीं रहता। यह पूरी प्रभार और संलग्नीकरण व्यवस्था की पारदर्शिता, एकरूपता और प्रशासनिक कसौटी का सवाल बन जाता है। बोड़ला में नई व्यवस्था लागू हो चुकी है, लेकिन प्रशासनिक गलियारों में चर्चा अभी भी जारी है। एक तरफ अधिकारी को क्षेत्र से हटाकर जिला पंचायत में संलग्न किया गया, दूसरी तरफ दूसरे विकासखंड में वर्षों से प्रभार की व्यवस्था कायम है। ऐसे में प्रशासनिक फैसलों का अलग-अलग पैमाना होने की धारणा को बल मिलना स्वाभाविक है। आदेश प्रशासन का है, लेकिन व्यवस्था की पारदर्शिता की जिम्मेदारी भी प्रशासन की ही है।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी,जलाशयों में 91 फीसदी से ज्यादा पानी, 7 लबालब

रायपुर। मौसम विभाग ने प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिर सकती है। अगले दो दिनों में भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटे में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग में कुछ जगह भारी, जबकि बस्तर और दुर्ग संभाग में एक-दो जगह बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश धनोरा में 140 मिमी और बस्तर में 100 मिमी दर्ज की गई है। इसके अलावा पखांजूर, नांगुर, कोंडागांव और अंतागढ़ में 90-90 मिमी पानी बरसा है। मानसून को प्रदेश में आए 82 दिन हो चुके हैं। 23 जून को दंतेवाड़ा के रास्ते प्रदेश में दाखिल हुए मानसून से अब तक अच्छी बारिश हुई है। 12 सितंबर तक प्रदेश में कुल 1001 मिमी पानी बरस चुका है। यह इस अवधि के सामान्य औसत 1041.1 मिमी से केवल 4 प्रतिशत कम है। लगातार बारिश के कारण प्रदेश के बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। प्रदेश के 46 प्रमुख और मध्यम जलाशयों में औसत जलभराव 91.10 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इनमें से सात जलाशय पूरी तरह भर चुके हैं, जबकि 18 अन्य जलाशयों में 90 प्रतिशत से ज्यादा पानी भरा हुआ है।

आम आदमी पार्टी ने अन्यतम शुक्ला को छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति किया

रायपुर। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम सहित 21 राज्यों लिए सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति की है। जिसका आदेश आप पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने जारी किया है। आदेश के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पार्टी ने अन्यतम शुक्ला को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया है। वहीं मध्यप्रदेश से अभिलाषा जैन और यूपी में विपिन कुमार पाठक को कमान सौपी गई है। अन्यतम शुक्ला ने नई जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूं. आज के दौर में सोशल मीडिया जनता की आवाज़ और सरकार की नीतियों के सच को सामने लाने का सबसे सशक्त माध्यम है. छत्तीसगढ़ के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की नीतियों, जनकल्याणकारी विचारों और अरविंद केजरीवाल की गारंटी को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम पूरी ईमानदारी से काम करेगी.

10.761 किलो गांजा के साथ ओडिशा के तीन तस्कर गिरफ्तार

रायपुर। जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ पुलिस की ए.एन.टी.एफ टीम एवं थाना सरिया पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफबड़ी कार्रवाई करते हुए 10.761 किलोग्राम गांजा के साथ ओडिशा के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गांजा, टोयोटा कार एवं दो मोबाइल सहित कुल ?8.26 लाख की संपत्ति जब्त की है। पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र पटेल एवं उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) संतोषी ग्रेस के मार्गदर्शन में 12 सितंबर 2026 को ए.एन.टी.एफ एवं थाना सरिया पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने थाना सरिया के सामने मेन रोड पर घेराबंदी कर ग्रे रंग की टोयोटा कार क्रमांक छ्त 05 ह 6165 को रोका। कार में सवार तीन व्यक्तियों से पूछताछ एवं तलाशी के दौरान उनकी गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने पर कार की जांच की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान श्याम बाबू चौधरी (28 वर्ष), विक्की सहनी (29 वर्ष) एवं जितेन्द्र चौधरी (32 वर्ष), सभी निवासी बरगढ़ जिला, ओडिशा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर सरिया मार्ग होते हुए प्रयागराज, उत्तर प्रदेश जा रहे थे। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे एवं वाहन के बोनट के अंदर बांधकर रखे गए 10 पैकेटों में कुल 10.761 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने गांजा के अलावा एक टोयोटा कार और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं।

साइबर जागृति अभियान से जुड़ें, 'जागरूकता की एक सेल्फी' लेकर साझा करें : सुरेंद्र शर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा प्रदेश को साइबर अपराध से मुक्त बनाने के संकल्प के साथ 15 अगस्त से 02 अक्टूबर 2026 तक विशेष 'साइबर जागृति अभियान' चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता श्री सुरेंद्र शर्मा ने आम नागरिकों, युवाओं एवं प्रबुद्धजनों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करने तथा अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने की अपील की है। श्री शर्मा ने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और इनसे बचाव का सबसे प्रभावी उपाय जागरूकता और सतर्कता है। उन्होंने नागरिकों से छत्तीसगढ़ पुलिस की इस पहल से जुड़ने और साइबर अपराधों के प्रति स्वयं जागरूक होने के साथ-साथ अपने परिवार, मित्रों एवं आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नागरिक क्क्र कोड स्कैन कर 'जागरूकता की एक सेल्फी' लें ।

मुख्यमंत्री ने जापानी विद्यार्थियों से किया आत्मीय संवाद

छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक,सांस्कृतिक विरासत से कराया परिचित

- भारत-जापान के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को शिक्षा और तकनीक दे रहे नया विस्तार : मुख्यमंत्री
- जापान की एहिमे यूनिवर्सिटी के 17 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की सौजन्य मुलाकात

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में जापान की एहिमे यूनिवर्सिटी से आए 17 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। भारत-जापान इंटर एक्सचेंज कार्यक्रम के अंतर्गत तीन दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर छत्तीसगढ़ पहुंचे विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री श्री साय ने आत्मीय संवाद किया। इस दौरान भारत और जापान के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों, बौद्ध विरासत, शिक्षा, अनुसंधान, तकनीकी नवाचार, स्टार्टअप तथा दोनों देशों के युवाओं के बीच बढ़ते संवाद सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जापानी छात्र-छात्राओं का छत्तीसगढ़ की धरती पर आत्मीय स्वागत करते हुए कहा कि भारत और जापान की मित्रता की जड़ें दोनों देशों की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में गहराई से जुड़ी हुई हैं। समय के साथ यह संबंध संस्कृति और आध्यात्मिकता से आगे बढ़कर शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, नवाचार और आर्थिक सहयोग के अनेक क्षेत्रों तक विस्तृत हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और जापान आज परंपरा और आधुनिकता के सुंदर समन्वय के साथ विश्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और सम्मान की

मजबूत नींव है। युवाओं तथा विद्यार्थियों के बीच इस प्रकार के शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से यह संबंध आने वाली पीढ़ियों में और अधिक मजबूत होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत भगवान बुद्ध की भूमि है। भगवान बुद्ध के शांति, करुणा, मैत्री और मानव कल्याण के संदेश ने दुनिया के अनेक देशों को प्रभावित किया और जापान की संस्कृति में भी बौद्ध दर्शन की गहरी छाप दिखाई देती है। यही साझा आध्यात्मिक विरासत भारत और जापान को एक विशिष्ट सांस्कृतिक सूत्र में जोड़ती है। उन्होंने जापानी विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ की समृद्ध पुरातात्विक विरासत की जानकारी देते हुए सिरपुर, मैनपाट और भोंगापाल जैसे महत्वपूर्ण स्थलों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महानदी के तट पर स्थित सिरपुर छत्तीसगढ़ की प्राचीन सभ्यता, कला, स्थापत्य और बौद्ध विरासत का अद्भुत केंद्र है। यहां प्राप्त पुरातात्विक अवशेष प्रदेश के गौरवशाली इतिहास और विभिन्न संस्कृतियों के समन्वय की कहानी बताते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक धरोहर को देश-दुनिया में नई पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सिरपुर को विश्वस्तरीय ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में भी योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि दुनिया के विभिन्न देशों से आने वाले विद्यार्थी, शोधार्थी और पर्यटक छत्तीसगढ़ आएं, यहां की विरासत को जानें और प्रदेश के साथ ज्ञान एवं संस्कृति का एक स्थायी संबंध स्थापित करें। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपनी जापान यात्रा से जुड़े अनुभव भी विद्यार्थियों के साथ साझा किए।

चाकूबाजों पर विशेष अभियान एक सप्ताह में 18 गिरफ्तार किए

- सात थाना क्षेत्रों में आर्म्स एक्ट के तहत 18 मामले दर्ज, धारदार चाकू और कटार बरामद

रायपुर। संवाददाता

सार्वजनिक स्थानों पर चाकूबाजी और अवैध हथियारों के प्रदर्शन पर अंकुश लगाने रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के सेंट्रल जोन में विशेष साप्ताहिक अभियान चलाया गया। 7 से 13 सितंबर तक चले अभियान में पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 18 प्रकरण दर्ज कर 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से धारदार चाकू और अन्य नुकीले हथियार बरामद किए गए। यह अभियान डीसीपी सेंट्रल जोन तारकेश्वर पटेल के निर्देश और एडिशनल डीसीपी विवेक शुक्ला के मार्गदर्शन में चलाया गया। पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लेकर घूमने और उनका प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। सिटी कोतवाली क्षेत्र में चार मामलों में आकाश नायक, गोलू यादव, शिवबहोर रजक और परमा साहू के खिलाफकार्रवाई की गई। गोलबाजार में मुकेश उर्फ मुक्कू नायक और सुनील ताण्डी के खिलाफ दो प्रकरण दर्ज किए गए। मौदहापारा थाना क्षेत्र में धन्नू साहू और रविन्द्र साठे के खिलाफदो कार्रवाई की गईं। दोनों के कब्जे से धारदार चाकू बरामद किए गए। गंज थाना क्षेत्र में पांच मामलों में नितेश सोनी, अशोक भांडेकर, मोहम्मद अरशद भिनसारा, नितिन हरिजन उर्फबिड़ी और शिवा नायक उर्फछुकरा के खिलाफ कार्रवाई हुई। इसी तरह सिविल लाइंस क्षेत्र में शुभम जाल और देवेंद्र नगर क्षेत्र में बंटी दीप उर्फ पनीरवाला के खिलाफ कार्रवाई की गई। देवेंद्र नगर मामले में धारदार नुकीला चाकू बरामद हुआ। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में तीन मामलों में शुभम सोनवानी, प्रतीक साहू और महेश सोना के खिलाफकार्रवाई की गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों से धारदार चाकू/कटार बरामद कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की।

स्नेक रेस्क्यू के दौरान स्नेक कैचर मनीष पाटिल की सर्पदंश से मौत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के नवागढ़ से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। स्नेक रेस्क्यू के दौरान जहरीले सांप के डसने से स्नेक कैचर मनीष पाटिल की मौत हो गई। मनीष 112 की टीम के साथ स्नेक रेस्क्यू के लिए नवागढ़ पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू के दौरान सांप को डिब्बे में डालते समय उसने मनीष पर हमला कर दिया और उन्हें डस लिया। सर्पदंश के बाद मनीष को तत्काल नवागढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें बिलासपुर के सिम्स अस्पताल रेफर किया गया। सिम्स में इलाज के दौरान मनीष पाटिल ने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि मनीष लंबे समय से स्नेक रेस्क्यू का काम कर रहे थे और अब तक हजारों सांपों का रेस्क्यू कर चुके थे।

बीजेपी के नाराज फूफा हमारे संपर्क में

बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा,कई नेता हमारे संपर्क में...

रायपुर/संवाददाता

बिलासपुर में कांग्रेस के तीन दिवसीय संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। अंतिम दिन दीपक बैज ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का संदेश दिया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने बीजेपी सरकार पर शराब बिक्री, आदिवासी हित, खनिज संपदा और कोल ब्लॉक आवंटन समेत कई मुद्दों पर निशाना साधा। बिलासपुर में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों के तीन दिवसीय संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया। शिविर के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने

ब्लॉक अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सरकार के खिलाफमैदान में उतरने की रणनीति पर मंथन किया गया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हमारा एक-एक कार्यकर्ता शिविर से अर्जुन बनकर निकल रहा है, जिसकी नजर सीधे मछली की आंख पर होगी। कार्यकर्ता बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करेंगे और सरकार के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। बैज ने कहा कि तीन दिन के मंथन से विष नहीं, बल्कि अमृत ही अमृत निकला है। शिविर के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अलग-अलग मुद्दों को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार को घेरा। मंत्री खुशवंत साहेब के भाई ढालदास साहेब के मसले पर बैज ने कहा, 'ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के कई नेता हाल में इस्तीफा दे चुके हैं। बहुत से बीजेपी नेता और कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं।

अब भूमि उपयोग नियमों में बड़ा बदलाव,छग में बदलेंगे नियम.....

- आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में विकास गतिविधियों को गति देने के लिए भूमि उपयोग से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल, स्पष्ट और व्यावहारिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्तावित संशोधन में विभिन्न भूमि उपयोग श्रेणियों के लिए 'नेगेटिव लिस्ट' आधारित व्यवस्था अपनाने का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था केंद्र सरकार के डीरिगुलेशन और अनुपालन बोझ कम करने से जुड़े व्यापक सुधारों के अनुरूप है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का निरंतर प्रयास है कि नागरिकों, उद्यमियों और निवेशकों के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए। इसके साथ ही विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है। भूमि उपयोग नियमों में प्रस्तावित संशोधन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बदलाव से बदलती जरूरतों के अनुरूप विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी। इससे प्रदेश में निवेश, रोजगार और अधोसंरचना विकास को गति मिलने की उम्मीद है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि सरकार का उद्देश्य नियमन को समाप्त करना नहीं है, बल्कि इसे अधिक स्पष्ट, सरल, लचीला और परिणामोन्मुख बनाना है। प्रस्तावित नेगेटिव लिस्ट आधारित व्यवस्था में प्रतिबंधित गतिविधियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाएगा। वहीं, प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए अनावश्यक नियामक बाधाओं को कम किया जाएगा। इससे भूमि उपयोग की व्यवस्था अधिक व्यावहारिक बन सकेगी और विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी। प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से मास्टर प्लान में निर्धारित विभिन्न भूमि उपयोगों को भी अधिक लचीला और समयानुकूल बनाया जा सकेगा।

शराब पीने के लिए पैसे मांगने वाले गुंडा बदमाश को भेजा जेल

रायपुर। आगामी त्योहारों और भीड़भाड़ के सीजन को देखते हुए पश्चिम जोन पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना आजाद चौक क्षेत्र में शराब पीने के लिए पैसे की उगाही करने और मारपीट करने के मामले में पुलिस ने एक गुंडा बदमाश को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। वहीं, दो अन्य बदमाशों के खिलाफप्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, 6 सितंबर 2026 को कृष्णा मरकाम उर्फ गोलू (25), निवासी बजरंग नगर, अन्नपूर्णा मंदिर के पास से मुकेश उर्फदादू साहू, निवासी हांडीपारा आजाद चौक, ने शराब पीने के लिए पैसे की मांग की थी। पैसे नहीं होने की बात कहने पर आरोपी ने कथित रूप से गाली-गलौज की और अपने साथी के साथ मिलकर लोहे की पाइप से मारपीट कर चोट पहुंचाई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 212/2026 के तहत धारा 119(1), 296 एवं 3(5) बीएनएस में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी मुकेश उर्फदादू साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इसी अभियान के तहत क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए मोहम्मद सैफी (21), निवासी ईदगाहभाठा और शेख जमील (26), निवासी ईदगाहभाठा, लाखेनगर के खिलाफ धारा 170, 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

उप मुख्यमंत्री ने मुड़घुसरी में 1.48 करोड़ रुपए के तीन सड़क का किया भूमिपूजन

- वनांचल में 15.40 किलोमीटर सड़कों का होगा निर्माण, विकास को मिलेगी नई रफ्तार
- बैगा बाहुल्य क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक सुगम पहुंच की मिलेगी सुविधा

रायपुर/ संवाददाता

वनांचल के गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड को बड़ी सौगात मिली है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने ग्राम मुड़घुसरी में 1.48 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले तीन सड़क मार्गों के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। कुल 15.40 किमी लंबाई के इन सड़क मार्गों के निर्माण से बैगा बाहुल्य क्षेत्र के ग्रामीणों का आवागमन आसान होगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार सहित अन्य जरूरी सेवाओं तक उनकी पहुंच बेहतर होगी। भूमिपूजन के अंतर्गत मुड़घुसरी से ठाकुरटोला मार्ग का 3.30 किलोमीटर, ठाकुरटोला से बांटीपथरा मार्ग का 4.00 किमी तथा सिंघारी से पांडातराई मार्ग का 8.40 किमी लंबाई में निर्माण किया जाएगा। इन मार्गों के बेहतर होने से वनांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा मजबूत होने के साथ ही क्षेत्र में विकास कार्यों और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि वनांचल क्षेत्रों का विकास शासन की प्राथमिकता है। सड़क सहित मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कर ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें ग्रामीणों के जीवन को आसान बनाने के साथ-साथ क्षेत्र में विकास की नई संभावनाओं का मार्ग भी खोलती है। सड़क मार्गों के नवीनीकरण से वनांचल के ग्रामीणों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। बेहतर सड़क सुविधा से विद्यार्थियों, मरीजों, किसानों और आम नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार तथा अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होगी। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। इस अवसर पर पूर्व संसदीय सचिव डॉ. सियाराम साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी, श्री नितेश अग्रवाल, जिला पंचायत सदस्य श्री राम कुमार भट्ट, नगर पंचायत अध्यक्ष बोड़ला श्री विजय पाटिल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री विदेशीराम धुर्वे, श्री संतोष पटेल, श्री मनीराम साहू, श्री भुनेश्वर चंद्राकर, श्री रामकिंकर वर्मा, श्री खिलेश्वर साहू सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी उपस्थित रहे।

जापान से आए एहिमे यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधिमंडल ने देखा छत्तीसगढ़ की प्राचीन विरासत का वैभव

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने 17 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय डेलीगेशन के लिए आयोजित विशेष हेरिटेज टूर...

- वैश्विक अकादमिक एवं पर्यटन संवाद में सिरपुर को नई पहचान दिलाने की पहल

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने जापान के मत्सुयामा स्थित एहिमे यूनिवर्सिटी के 17 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के लिए विशेष हेरिटेज टूर का आयोजन किया। अकादमिक एवं शोध सहयोग के उद्देश्य से 12 से 14 सितंबर 2026 तक

एनआईटी रायपुर द्वारा होस्ट किए गए जापानी डेलीगेशन ने 14 सितंबर को प्राचीन ऐतिहासिक नगरी सिरपुर का भ्रमण कर छत्तीसगढ़ की उस विरासत को करीब से जाना, जिसमें बौद्ध, हिंदू और जैन संस्कृति का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। मुख्य हॉस्पिटैलिटी एवं आयोजन सहयोगी के रूप में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के लिए सिरपुर में विशेष हेरिटेज टूर की व्यवस्था की। डेलीगेशन को सिरपुर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्थापत्य कला, पुरातात्विक महत्व और धार्मिक-सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराने के लिए विशेषज्ञ स्थानीय गाइड की सेवाएं ली गईं। साथ ही जापानी मेहमानों की खान-पान संबंधी पसंद को ध्यान में रखते हुए विशेष हॉस्पिटैलिटी एवं भोजन की व्यवस्था भी की गई। महानदी के तट पर बसा सिरपुर प्राचीन काल में श्रीपुर के नाम से जाना जाता था और दक्षिण कोसल की राजधानी के रूप में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा। वर्तमान सिरपुर में हुए पुरातात्विक उत्खननों से बौद्ध विहारों, हिंदू मंदिरों, जैन अवशेषों तथा अन्य प्राचीन संरचनाओं का विस्तृत संसार सामने आया है। यहां बौद्ध, हिंदू और जैन परंपराओं से जुड़े अनेक पुरातात्विक अवशेष मौजूद हैं। जापानी प्रतिनिधिमंडल ने इस ऐतिहासिक नगरी के प्रमुख विरासत स्थलों का भ्रमण करते हुए यहां की स्थापत्य परंपरा और प्राचीन सांस्कृतिक जीवन को समझा।

संपादकीय

न्यायाधीशों की नियुक्ति पर केंद्र-राज्य टकराव, आखिर प्रक्रिया में कहां है पेच?

केंद्र सरकार ने पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अश्वनी कुमार मिश्रा का नाम अधिसूचित किया था। मगर पंजाब सरकार ने यह आरोप लगाया कि केंद्र ने यह कदम राज्य सरकार की राय का इंतजार किए बिना संवैधानिक नियमों तथा तय प्रक्रियाओं को दरकिनार करके उठाया। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के बीच अलग-अलग मसलों पर खींचतान एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। असहमति और आलोचना लोकतंत्र की बुनियाद को और ज्यादा मजबूत ही करती है। मगर सभी पक्षों की यह कोशिश होनी चाहिए कि इस द्वंद्व की छाया कम से कम न्यायपालिका पर नहीं पड़े।विडंबना यह है कि कई बार न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर भी ऐसे टकराव सामने आते हैं, जिससे किसी खास मामले में इससे संबंधित पूरी प्रक्रिया कठघरे में खड़ी होती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अश्वनी कुमार मिश्रा का नाम अधिसूचित किया था। मगर पंजाब सरकार ने यह आरोप लगाया कि केंद्र ने यह कदम राज्य सरकार की राय का इंतजार किए बिना संवैधानिक नियमों तथा तय प्रक्रियाओं को दरकिनार करके उठाया।इस मसले पर अब केंद्र और पंजाब सरकार आमने-सामने हैं। टकराव की तीव्रता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि रविवार को पंजाब मंत्रिमंडल ने इस नियुक्ति को अधिसूचित करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया।जाहिर है, इस मसले पर अब यह विवाद खड़ा हो गया है कि क्या इसमें प्रक्रिया संबंधी कोई अनदेखी हुई है। हालांकि केंद्र का यह कहना है कि राज्य सरकार की राय लेना जरूरी है, लेकिन वह बाध्यकारी नहीं है। इसके बाद पंजाब सरकार के विरोध को दरकिनार करते हुए न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा को उनके नए पद पर शपथ दिला दी गई, मगर एक बार फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद और राज्य की शक्तियों को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े हुए हैं, उन पर स्पष्टता की जरूरत है।आखिर क्या वजह है कि जहां किसी मामले में केंद्र और राज्य की सहभागिता एक लोकतांत्रिक तकाजा है, वहां कई बार खासतौर पर उन राज्यों की सरकारें खुद को उपेक्षित महसूस करती हैं, जहां विपक्षी दल सत्ता में होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अगर राज्य की कोई भूमिका है, तो उसे महत्त्व देना लोकतंत्र को मजबूती ही देगा। यों भी, इस संबंध में कोई फैसला करते हुए क्या यह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि किसी राज्य की ओर से संवैधानिक अधिकारों को दबाने का आरोप न लगे या कोई अप्रिय विवाद न खड़ा हो!

यहां भ्रष्टाचार की बात करते समय एक सावधानी भी जरूरी है। किसी अधिकारी या व्यवसायी को बिना जांच दोषी ठहराना उचित नहीं। लेकिन यदि जांच में यह सिद्ध होता है कि नियमों के विरुद्ध निर्माण को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, निरीक्षण में लापरवाही हुई या किसी प्रकार की मिलीभगत रही, तो जिम्मेदारी केवल भवन मालिक तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जिसने नियम तोड़े और जिसने नियम तोड़ने दिए-दोनों को जवाबदेह बनाना होगा। सत्य निकेतन की त्रासदी को जुलाई 2024 के पुराने राजेंद्र नगर हादसे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वहां राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों-तनीया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डालविन की मृत्यु हुई थी।

सत्य निकेतन हादसा- जिम्मेदार अधिकारियों पर हो ठोस कार्रवाई

(ललित गर्ग)

सरकारी भवन भी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी किस पर भरोसा करे? मई 2024 में दिल्ली के आईटीओ स्थित सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग में आग लगी थी। 46 वर्षीय ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की धुएं में दम घुटने से मृत्यु हुई थी। रिपोर्टों के अनुसार भवन पुराना था और उसमें आधुनिक फायर-स्प्रिंकलर व्यवस्था भी नहीं थी। दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार को पांच मंजिला छात्र-पीजी भवन का भरभराकर गिर जाना केवल एक दर्दनाक हादसा नहीं है। यह उस व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न है, जो भवन बनने देती है, उसमें अनधिकृत निर्माण होने देती है, उसमें विद्यार्थियों को रहने देती है, उसकी कमजोरियों को वर्षों तक नजरअंदाज करती है और फिर उसके ढह जाने के बाद जागती है। इस हादसे में अब तक छह लोगों की मौत की सूचना है और कई लोग घायल हुए हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार भवन में बेसमेंट और कई ऊपरी मंजिलों में मरम्मत या निर्माण संबंधी काम चल रहा था। प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच और भवन मालिक के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि हादसे के बाद किसके खिलाफ एफआईआर होगी? असली सवाल यह है कि हादसे से पहले जिम्मेदार अधिकारी कहां थे? यदि निर्माण नियमों का उल्लंघन था, यदि भवन का स्वीकृत नक्शा नहीं था, यदि अतिरिक्त मंजिलें बनाई गई थीं, यदि बेसमेंट में निर्माण चल रहा था, यदि भवन छात्रों के रहने के लिए इस्तेमाल हो रहा था और यदि वह संरचनात्मक रूप से जोखिमपूर्ण था, तो इन सबका पता प्रशासन को तब क्यों नहीं चला जब वहां निर्माण हो रहा था? सत्य निकेतन दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के आसपास विद्यार्थियों का प्रमुख इलाका है। देश के विभिन्न राज्यों से हजारों युवा यहां अपने भविष्य के सपने लेकर आते हैं। वे छोटे-छोटे कमरों, पीजी और किराये के मकानों में रहकर पढ़ते हैं। उनके माता-पिता अपनी जीवनभर की कमाई का बड़ा हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर लगाते हैं और यह विश्वास करते हैं कि राजधानी में उनका बच्चा सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब शिक्षा की तलाश में निकला युवा एक ऐसी इमारत में पहुंचता है, जिसकी नींव ही नियमों और सुरक्षा के साथ समझौते पर टिकी हो, तो विकास की हमारी पूरी अवधारणा कटघरे में खड़ी हो जाती है और यह कोई पहली चेतावनी नहीं है। 2022 में भी सत्य निकेतन में निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत ढहने से दो मजदूरों की मौत हुई थी और चार लोग घायल हुए थे। उस समय भी निर्माण कार्य, सुरक्षा और भवन की निगरानी पर सवाल उठे थे। लगभग चार साल बाद उसी इलाके में फिर एक बड़ी इमारत ढह गई। इसका अर्थ है कि हमने घटना से सबक लेने के बजाय घटना को एक समाचार की तरह देखा और आगे बढ़ गए। यहां भ्रष्टाचार की बात करते समय एक सावधानी भी जरूरी है। किसी अधिकारी या व्यवसायी को बिना जांच दोषी ठहराना उचित नहीं। लेकिन यदि जांच में यह सिद्ध होता है कि नियमों के विरुद्ध निर्माण को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, निरीक्षण में लापरवाही हुई या किसी प्रकार की मिलीभगत रही, तो जिम्मेदारी

केवल भवन मालिक तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जिसने नियम तोड़े और जिसने नियम तोड़ने दिए-दोनों को जवाबदेह बनाना होगा। सत्य निकेतन की त्रासदी को जुलाई 2024 के पुराने राजेंद्र नगर हादसे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वहां राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों-तनीया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डालविन की मृत्यु हुई थी। सबसे भयावह तथ्य यह था कि बेसमेंट का उपयोग लाइब्रेरी के रूप में हो रहा था, जबकि उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार उसे पार्किंग और स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इससे भी अधिक चिंताजनक बात सामने आई-हादसे से लगभग एक महीने पहले एक विद्यार्थी ने एमसीडी में शिकायत की थी। भारत में भवन निर्माण के लिए नियमों की कमी नहीं है। नक्शा स्वीकृति, भवन उपविधियां, अग्नि सुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षा, अधिभोग प्रमाणपत्र, पार्किंग, बेसमेंट के उपयोग-हर क्षेत्र के लिए नियम हैं। लेकिन समस्या नियमों की संख्या नहीं, उनके पालन की ईमानदारी है। जब किसी भवन में एक मंजिल की अनुमति हो और चार-पांच मंजिलें खड़ी हो जाएं, जब बेसमेंट स्टोरेज के लिए स्वीकृत हो और वहां लाइब्रेरी या व्यावसायिक गतिविधि चलने लगे, जब सड़क की जलनिकासी बाधित हो और फिर भी निर्माण चलता रहे-तो सवाल केवल नागरिक की मनमानी का नहीं है। सवाल उस पूरी निगरानी व्यवस्था का है, जो आंखों के सामने होने वाले बदलाव को देखने के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं करती। भ्रष्टाचार केवल रिश्वत लेने का नाम नहीं है। भ्रष्टाचार वह भी है जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति अपने कर्तव्य को जानबूझकर न निभाए। किसी अवैध निर्माण को देखकर आंखें बंद कर लेना भी व्यवस्था के प्रति अपराध है। किसी भवन को जोखिमपूर्ण जानते हुए कार्रवाई न करना भी भ्रष्ट प्रशासनिक संस्कृति का हिस्सा है। सरकारी भवन भी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी किस पर भरोसा करे? मई 2024 में दिल्ली के आईटीओ स्थित सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग में आग लगी थी। 46 वर्षीय ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की धुएं में दम घुटने से मृत्यु हुई थी। रिपोर्टों के अनुसार भवन पुराना था और उसमें आधुनिक फायर-स्प्रिंकलर व्यवस्था भी नहीं थी। यह घटना एक और सवाल सामने रखती है-जब सरकारी भवनों में भी सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, तो निजी और अनधिकृत भवनों की निगरानी की स्थिति क्या होगी? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और देश के अन्य महानगरों में अनियोजित शहरी विस्तार लगातार बढ़ रहा है। जमीन सीमित है, जनसंख्या बढ़ रही है, किराये की मांग बढ़ रही है और व्यावसायिक हित अधिकतम जगह का अधिकतम उपयोग चाहते हैं। ऐसे में यदि शासन मजबूत नियमन और वैज्ञानिक शहरी नियोजन नहीं करेगा तो शहर ऊपर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा नीचे गिरती जाएगी। दुर्घटना के बाद वही परिचित दृश्य सामने आता है-मंत्री घटनास्थल पर पहुंचते हैं, अधिकारी बैठक करते हैं, मुआवजे की घोषणा होती है, जांच समिति बनती है, कुछ भवन सील होते हैं, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं और कुछ दिनों तक प्रशासन सक्रिय दिखाई देता है। फिर धीरे-धीरे सब सामान्य हो जाता है। लेकिन किसी मृत विद्यार्थी के माता-पिता के लिए कुछ भी सामान्य नहीं होता। उनके लिए वह एक जांच समिति नहीं, जीवनभर का खालीपन है। उनके लिए मुआवजे की राशि उनके बेटे या बेटी का विकल्प नहीं है। वे यह जानना चाहते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित क्यों नहीं था? किसने सुरक्षा की गारंटी दी थी? किसने निगरानी की थी? किसने खतरे को नजरअंदाज किया था? इसलिए जांच का उद्देश्य केवल दोषी व्यक्ति ढूंढना नहीं होना चाहिए। जांच को यह भी पता लगाना चाहिए कि किस स्तर पर सिस्टम विफल हुआ। फाइल कहां रुकी? निरीक्षण किसने किया? शिकायत किसने दबाई? नक्शा किस आधार पर स्वीकार हुआ? अवैध निर्माण वर्षों तक कैसे चलता रहा? भवन में रहने वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? और सबसे महत्वपूर्ण-क्या उन अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी जिनकी जिम्मेदारी ही ऐसे हादसों को रोकना थी? सत्य निकेतन के मलबे से आज देश को केवल छह मौतों का आंकड़ा नहीं देखना चाहिए। वहां दबे हुए सपनों को देखना चाहिए। उन माता-पिताओं की आंखों को देखना चाहिए जिन्होंने अपने बच्चों को दिल्ली भेजते समय यह सोचा होगा कि वे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और परिवार का नाम रोशन करेंगे। उन सपनों की मौत केवल एक इमारत के गिरने से नहीं हुई है, वे उस मानसिकता के नीचे दबे हैं जिसमें नियमों से अधिक प्रभावशाली पैसा, सुविधा और 'सब चलता है' की संस्कृति बन जाती है। अब समय है कि सरकारें हादसों के बाद जागने की आदत छोड़ें। भवन गिरने से पहले निरीक्षण हो, पानी भरने से पहले जलनिकासी सुधरे, शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई हो और भ्रष्टाचार होने से पहले ही उसकी गुंजाइश बंद हो। क्योंकि देश को केवल नया भारत नहीं बनाना है-उसे सुरक्षित, जिम्मेदार, ईमानदार और संवेदनशील भारत भी बनाना है।

जिंदगी में छोटा हिस्सा ही होना चाहिए सोशल मीडिया, दुरुपयोग रोकने के लिए कदम उठाने होंगे

(कल्याणी चौधरी)

सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज, साइबर अपराध, और नफरत फैलाने वाली पोस्ट पर रोक लगाना सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।सोशल मीडिया आज हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। खबरों और सूचनाओं से लेकर मनोरंजन, शिक्षा और लोगों से जुड़ने तक, इसके बहुत से फायदे हैं। लेकिन इसके बढ़ते इस्तेमाल के साथ कई नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। सोशल मीडिया सूचनाओं को हम तक पहुंचाना आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ फेक न्यूज, साइबर अपराध, मानसिक तनाव, निजता और ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी बढ़ी हैं। ऐसे में सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना और इससे जुड़ी चुनौतियों को समझना बेहद जरूरी हो गया है। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग कई बार खबरों की सच्चाई जानने की मेहनत भी नहीं करते, उसके बजाय वायरल हो रही पोस्टों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। किसी पोस्ट, वीडियो या मैसेज को बिना जांच करें उसकी बिना पुष्टि करे आगे शेयर भी कर देते है और इससे गलत जानकारी और अफवाहें तेजी से फैलती हैं। कई बार लोग इसे असली समाचार से मिलाकर देखने की भी जहमत नहीं उठाते, जिससे लोगों के बीच भ्रम पैदा होता है।

बच्चों की सुरक्षा एक गंभीर चुनौती – सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा भी एक गंभीर चुनौती बन गई है। कम उम्र में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले बच्चे अनजान या अजनबी लोगों के संपर्क में आ सकते हैं या अनुचित सामग्री के संपर्क में आ सकते हैं। इसलिए बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर निगरानी और जागरूकता बताने चाहिए। इसी वजह से कई देशों में बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए नियम भी बनाए गए हैं। आज बहुत से लोग घंटों फोन और सोशल मीडिया स्क्रीन से जुड़े रहते हैं। धीरे-धीरे ये फोन की आदत लत में बदल सकता है। इसके कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित होती है और पढ़ाई, काम, नींद और दूसरी जरूरी गतिविधियों के लिए समय कम पड़ने लगता है और कई बार शरीर में बीमारियां भी घर बना लेती हैं। सोशल मीडिया अब दिखावे की दुनिया हो गई है। लोग अपनी जिंदगी के अच्छे पल ही दूसरों के सामने रखते हैं। ऐसे में दूसरे लोगों की जिंदगी देखकर व्यक्ति खुद की तुलना उनसे करने लगता है, खुद को कम आंकने लगते है, बेहतर दिखने और दूसरों से आगे निकलने की वजह से वो तनाव और हीन भावना के शिकार हो जाते है।

ठगी का आसान जरिया बना सोशल मीडिया – सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल में बड़े-बुजुर्गों को भी कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। तकनीक और ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी न होने के कारण वे फर्जी लिंक, संदेश, कॉल या ऑनलाइन ठगी में फंस सकते हैं। इसलिए इस वर्ग को साइबर फ्रॉड और डिजिटल सुरक्षा के तरीकों के बारे में बताना जरूरी है। प्राइवेसी (निजता) का खतरा भी सोशल मीडिया की बड़ी चुनौतियों में शामिल है। आज लोग अपनी निजी तस्वीरें, लोकेशन, यात्रा, परिवार और दूसरी पर्सनल जानकारियां तुरंत से साझा कर देते हैं। अगर यह जानकारी गलत हाथों में पहुंच जाए तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इससे व्यक्ति की निजता के साथ-साथ उसकी व्यक्तिगत और डिजिटल सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो जाता है।सोशल मीडिया पर गाली-गलौज, ट्रोलिंग, धमकी और ऑनलाइन उत्पीड़न यानी साइबर बुलिंग की घटनाएं भी बढ़ती ही जा रही हैं।

पारिवारिक रिश्तों पर भी देखने को मिल रहा असर – सोशल मीडिया का असर पारिवारिक रिश्तों पर भी देखने को मिल रहा है। पहले परिवार के लोग साथ बैठकर खाना खाते, बातचीत करते और अपना समय एक-दूसरे के साथ बिताते थे। अब कई बार एक ही घर में रहने वाले लोग भी अपने-अपने फोन में व्यस्त रहते हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने के कारण आमने-सामने बातचीत कम हो जाती है। एआई तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ डीपफेक वीडियो, तस्वीरें और नकली आवाजें बनाना भी बहुत आसान हो गया है। किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज या वीडियो में बदलाव करके गलत और झूठ कंटेंट तैयार किया जा सकता है जो देखने में असली लगे।ऐसे कंटेंट का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने के लिए हो सकता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तस्वीर या वीडियो पर तुरंत विश्वास या कुछ शेयर करने के बजाय उसकी पुष्टि करना जरूरी है और।

तेजी से वायरल होती हैं भड़काऊ चीजें – सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली भाषा और भड़काऊ चीजें भी तेजी से फैलती है। कई बार किसी समूह या व्यक्ति के खिलाफ उल्टी सीधी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। इससे लोगों के बीच तनाव और विवाद बढ़ने का खतरा रहता है।फेक न्यूज, साइबर अपराध, और नफरत फैलाने वाली पोस्ट पर रोक लगाना सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। सरकार को लोगों की सुरक्षा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाने होते हैं, लेकिन इसके साथ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि लोगों की स्वतंत्रता प्रभावित न हो।

इसरो को कमजोर करने की साजिश हो रही या भारत को स्पेश सुपरपावर बनने की रणनीति पर काम चल रहा?

यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब इसरो के नौ कर्मचारी संगठनों ने 4 सितंबर को इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन को पत्र लिखकर अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रहे सुधारों, उत्पादन गतिविधियों के निजी कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों को हस्तांतरण तथा कर्मचारियों के भविष्य पर गंभीर सवाल उठाए थे। उनकी चिंता का केंद्र 21 अगस्त को आईएन एसपीएसी के अध्यक्ष पवन गोयनका की वह टिप्पणी थी, जिसमें कहा गया था कि भविष्य में इसरो प्रक्षेपण यानों का निर्माण बंद कर सकता है और उनका उत्पादन उद्योग या पीएसयू संभाल सकते हैं।

(नीरज कुमार दुबे)

विपक्ष ने भी इस मुद्दे को राजनीतिक मोर्चे पर उठा लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के नाम पर इसरो की भूमिका सीमित की जा रही है और उसकी दशकों पुरानी क्षमताएं निजी कंपनियों को सौंपी जा सकती हैं।

क्या भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को धीरे-धीरे निजी हाथों के हवाले किया जा रहा है, या फिर देश एक ऐसी नई अंतरिक्ष रणनीति की ओर बढ़ रहा है जिसमें इसरो शोध और सामरिक अभियानों का कमांड सेंटर बनेगा और उद्योग उत्पादन की ताकत? यही सवाल पिछले कुछ दिनों से भारतीय अंतरिक्ष जगत के भीतर और बाहर तेज बहस का विषय बना हुआ है। अब इसरो ने स्वयं सामने आकर स्पष्ट किया है कि न तो इसरो का निजीकरण होगा और न ही उसकी भूमिका या महत्व कम किया जाएगा।

यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब इसरो के नौ कर्मचारी संगठनों ने 4 सितंबर को इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन को पत्र लिखकर अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रहे सुधारों, उत्पादन गतिविधियों के निजी कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों को हस्तांतरण तथा कर्मचारियों के भविष्य पर गंभीर सवाल उठाए थे। उनकी चिंता का केंद्र 21 अगस्त को आईएन एसपीएसी के अध्यक्ष पवन गोयनका की वह टिप्पणी थी, जिसमें कहा गया था कि भविष्य में इसरो प्रक्षेपण यानों का निर्माण बंद कर सकता है और उनका उत्पादन उद्योग या पीएसयू संभाल सकते हैं।

इसरो का जवाब स्पष्ट है कि भूमिका बदल रही है, महत्व नहीं। एजेंसी अब उस दिशा में अपने वैज्ञानिक संसाधन केंद्रित करना चाहती है जहां उसकी विशेषज्ञता सबसे निर्णायक है। यानि फ्रंटियर रिसर्च, उन्नत प्रौद्योगिकी, मानव अंतरिक्ष उड़ान, अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान, गहरे अंतरिक्ष और ग्रहों के मिशन तथा राष्ट्रीय और सामरिक क्षमताएं। हम आपको बता दें कि संचार, नेविगेशन और पृथ्वी अवलोकन के उन्नत पेलोड, सेंसर, प्रणोदन प्रणालियां और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकें इसरो के मूल फोकस में बनी रहेंगी।

दूसरी ओर, जिन तकनीकों ने परिपक्वता हासिल कर ली है और जिनका बड़े पैमाने पर नियमित उत्पादन संभव है, उन्हें उद्योग और पीएसयू प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाओं के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। इसमें परिपक्व लॉन्च

व्हीकल, नियमित उपग्रह और स्थापित अंतरिक्ष प्रणालियां शामिल हो सकती हैं। इसरो का तर्क है कि इससे उसके वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों का समय उत्पादन में नहीं, बल्कि भविष्य की जटिल तकनीकों और महत्वाकांक्षी अभियानों में लगेगा।

यही इस बदलाव का सबसे बड़ा रणनीतिक अर्थ है। अंतरिक्ष शक्ति बनने के लिए इसरो को फैक्ट्री से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी फ्रंटियर पर खड़ा होना होगा। भारत ने 2030 तक सालाना 50 प्रक्षेपणों का लक्ष्य रखा है। पवन गोयनका का कहना है कि इतने बड़े पैमाने का लक्ष्य कोई एक संगठन अकेले हासिल नहीं कर सकता। इसके लिए निजी पूंजी, औद्योगिक उत्पादन क्षमता, उद्यमिता और वैश्विक बाजार तक पहुंच जरूरी है।

यह पूरी व्यवस्था भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 और एफडीआई नीति के क्रमिक उदारीकरण से जुड़ी है। इसरो इसे निजीकरण नहीं, बल्कि इकोसिस्टम विस्तार और क्षमता गुणन बता रहा है। उद्योग, स्टार्ट-अप और अकादमिक संस्थानों को अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला में शामिल कर इसरो की क्षमताओं को प्रतिस्थापित नहीं, बल्कि कई गुना करने की योजना है।

नई संरचना में विभागीय भूमिकाएं भी स्पष्ट की गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस नीति दिशा देगा, इसरो उन्नत अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और राष्ट्रीय मिशनों का मुख्य केंद्र रहेगा, आईएन- एसपीएसी गैर-सरकारी संस्थाओं की भागीदारी को सक्षम और अधिकृत करेगा, जबकि एनएसआईएल परिपक्व क्षमताओं के व्यावसायीकरण और उद्योग-आधारित उपयोग को आगे बढ़ाएगा।

लेकिन इस परिवर्तन पर सवाल खत्म नहीं हुए हैं। कर्मचारी संगठनों ने पूछा है कि नीति का कानूनी और प्रशासनिक आधार क्या है, इसका क्रियान्वयन कब होगा और मौजूदा कर्मचारियों तथा भविष्य की भर्ती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उनका सबसे महत्वपूर्ण तर्क है कि दशकों में विकसित इसरो की तकनीक राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए उसका हस्तांतरण पारदर्शी, जवाबदेह और सामरिक तथा सुरक्षा हितों के अनुरूप होना चाहिए।

विपक्ष ने भी इस मुद्दे को राजनीतिक मोर्चे पर उठा लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के नाम पर इसरो की भूमिका सीमित की जा रही है और उसकी दशकों पुरानी क्षमताएं निजी कंपनियों को सौंपी जा सकती हैं। पार्टी नेता जयराम रमेश ने इसे इसरो के साराभाई-धवन ढांचे को कमजोर करने की प्रक्रिया बताया।

यह विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं अब असाधारण स्तर पर पहुंच चुकी हैं। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, 2040 तक भारतीय मानवयुक्त चंद्र मिशन, पुन: प्रयोज्य और अगली पीढ़ी के लॉन्च सिस्टम तथा सतत चंद्र और ग्रह अन्वेषण, ये लक्ष्य साधारण व्यावसायिक विस्तार से हासिल नहीं होंगे। इसरो का कहना है कि ऐसी क्षमताओं को केवल बाजार की ताकतों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

हम आपको बता दें कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था फिलहाल लगभग 8.4 अरब डॉलर आंकी गई है और लक्ष्य 2033 तक इसे 44 अरब डॉलर तक पहुंचाने का है। इसलिए असली चुनौती निजी क्षेत्र बनाम इसरो नहीं, बल्कि इसरो-नेतृत्व वाले राष्ट्रीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की सफलता है। रणनीतिक दृष्टि से यह भारत के लिए निर्णायक मोड़ है। अब सवाल यह है कि क्या भारत उत्पादन का विस्तार करते हुए अपनी संवेदनशील तकनीक, सामरिक स्वायत्तता और वैज्ञानिक नेतृत्व को सुरक्षित रख पाएगा। यदि संतुलन सही बैठा, तो निजी उद्योग इसरो की ताकत बढ़ाएगा; यदि पारदर्शिता और संस्थागत नियंत्रण कमजोर पड़े, तो राष्ट्रीय क्षमताओं के हस्तांतरण पर उठ रहे सवाल और गंभीर होंगे। इसरो ने फिलहाल अपना संदेश साफ कर दिया है कि वह पीछे नहीं हट रहा, बल्कि उत्पादन की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अंतरिक्ष की अगली सीमा पर छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

बूथ-बूथ पहुंचेगा सेवा संकल्प, 17 सितंबर को हर बूथ पर जलेंगे दीप

मोदी के जन्मदिवस को सेवा गतिविधियों से जोड़ने भाजपा बस्तर मंडल ने बनाई रणनीति

बस्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर को भाजपा बस्तर मंडल बूथ स्तर पर सेवा संकल्प अभियान के रूप में मनाएगा। अभियान की तैयारियों को लेकर नगर पंचायत बस्तर में मंडल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें कार्यक्रम को केवल औपचारिक आयोजन तक सीमित रखने के बजाय प्रत्येक बूथ तक संगठन की सक्रियता पहुंचाने पर जोर दिया गया।बैठक में तय किया गया कि 17 सितंबर को बस्तर मंडल के सभी बूथों पर दीप प्रज्वलन किया जाएगा। इसके साथ ही सेवा संकल्प से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की यात्रा और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी।बैठक में बूथों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा गया कि संगठन की मजबूती का आधार बूथ स्तर का कार्यकर्ता है। ऐसे में अभियान के दौरान बूथ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय के साथ योजनाओं का संदेश समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा, सुशासन और राष्ट्रहित को प्रमुखता मिली है। सेवा संकल्प अभियान के जरिए इन कार्यों और योजनाओं को लेकर लोगों के बीच संवाद बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए मंडल स्तर से बूथवार तैयारियों पर नजर रखने और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में मंडल अध्यक्ष सुखदेव मंडावी, जिला पंचायत सदस्य शकुंतला कश्यप, पूर्व जिला उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप, पूर्व मंडल अध्यक्ष उदबो राम नाग, पार्षदगण सहित भाजपा मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

गोचर भूमि खाली करनी चाहिए सभी को जहां गौमाता सुख से रह सके: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी

बेमेतरा। जिला के ग्राम सलधा जहां सवा लाख शिवलिंग का ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है वहीं उत्तराम्नाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य भव्य चातुर्मास चल रहा है। सर्व प्रथम समस्त ग्रामवासी गोता माटरा के द्वारा पादुका पूजन किया गया। दण्डी स्वामी ज्योतिर्मयानंद सरस्वती जी महाराज ने सलधा शिवलिंग स्थापित करने वाले भक्तों के नाम की घोषणा की। अप्रमेय स्वामी जी ने विरुदावली का वाचन किया। परम पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा की धर्म यद्यपि हमारे अंदर प्रविष्ट करा के भेजा गया है हम सब धार्मिक हैं शायद कोई अधार्मिक हो । जो उत्थान चाहता है वो धार्मिक है। धर्म से उत्थान होता है और अधर्म से पतन। जो चीज हमको गिराती है उससे बच के रहें। इसलिए पाप को समझना होगा। 18 पुराण और 18 उप पुराण है। 36 हो गये। हमारा छत्तीसगढ़ है। श्री व्यास जी कहते हैं कि 18 पुराणों से दो बार व्यास भगवान ने कही कि पुण्य करो और पाप से बचो। पाप का अर्थ क्या है बच के रहो पाप से। इसे ही धर्म-अधर्म, शुभ-अशुभ भी कहते हैं। धर्म ऐच्छिक नहीं है मानना होगा यदि पाप से बचना है तो धर्म को मानन ही पड़ेगा बिना धर्म माने पाप से बच नहीं सकते। महाभारत में आया जो धर्म को मारता है धर्म उसे मारता है जो धर्म पालन के द्वारा धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म की उपेक्षा मत करो धर्म का पालन करो। पुण्य याने पवित्रता, परोपकार। पाप और पुण्य तीन प्रकार का होता है कायिक, वाचिक और मानसिक। चार प्रकार के कायिक पाप है पहला है अभक्ष्य भक्षण गलत चीज मत खाओ, जैसा अन्न वैसा मन गलत खाने से इसलिए रोका जाता है कि गलत खाने से मन और बुद्धि खराब हो जाती है गलत बुद्धि से गलत निर्णय होगा जिसका प्रभाव समाज में होगा समाज को दुख मिलेगा इसलिए गलत खाने से रोका जाता है। दूसरे की हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो चोरी करना बड़ा पाप है क्योंकि धन को शरीर का बाहरी प्राण कहा जाता है। वाचिक पाप बिना मतलब फालतु नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, किसी को कष्ट मिले ऐसा ना बोले, किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए।

16 सितंबर को तहसील स्तर पर किसान आंदोलन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन

भारतीय किसान संघ बस्तर ने किसानों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की

जगदलपुर। भारतीय किसान संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्देशानुसार किसान हितैषी मांगों को लेकर 16 सितंबर 2026, बुधवार को प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इसके तहत भारतीय किसान संघ जिला बस्तर की सभी तहसीलों में तहसील स्तर पर आंदोलन एवं ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक तहसील में भारतीय किसान संघ की तहसील कार्यकारिणी द्वारा तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। संगठन ने किसान हित से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित इस आंदोलन में अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है।भारतीय किसान संघ जिला बस्तर के जिलाध्यक्ष नील कुमार बघेल ने जिले के सभी तहसील अध्यक्ष, तहसील मंत्री, कार्यकारिणी सदस्यों एवं ग्राम इकाई के कार्यकर्ताओं से अपने-अपने क्षेत्र के किसानों के साथ आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि तहसील प्रभारी एवं सह-प्रभारी के नेतृत्व में आयोजित होने वाले ज्ञापन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संगठन के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सक्रिय रूप से जुटें।संगठन ने अपने आह्वान में कहा है कि ÷जो किसान हित में काम करेगा, वही देश में राज करेगा।÷ आंदोलन को लेकर जिला बस्तर की तहसीलों में तैयारियां की जा रही हैं।

नौकरी के नाम पर ठगी का जाल, बीजापुर पुलिस ने युवाओं को किया सतर्क

बीजापुर। नौकरी दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगी करने वालों से युवाओं और श्रमिकों को सावधान करने बीजापुर पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जागरूकता अभियान शुरू किया है। साइबर जागृति अभियान के पांचवें सप्ताह में 13 से 19 सितंबर तक जॉब फ्रॉड और फिशिंग के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि ठग फर्जी नौकरी के विज्ञापन, ऑनलाइन जॉब ऑफर और भर्ती एजेंसी के नाम पर रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन या नौकरी लगवाने के लिए पैसे मांग सकते हैं। ऐसे ऑफर पर भरोसा करने से पहले संबंधित कंपनी या संस्था की जानकारी उसके आधिकारिक स्रोत से जांचने की सलाह दी गई है।

पुलिस ने अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने और ओटीपी, बैंक डिटेल, एटीएम पिन व यूपीआई पिन किसी से साझा नहीं करने की अपील की है।

करंजी उचित मूल्य दुकान में चार माह से गुड़-चना नहीं मिलने का आरोप

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विभाग से जांच और शीघ्र वितरण की मांग

कोण्डागांव -कोंडागांव। ग्राम पंचायत करंजी स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोंडागांव के अध्यक्ष संजय करन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जानकारी ली, इस दौरान हितग्राहियों से चर्चा में पिछले चार माह से गुड़ एवं चना का वितरण नहीं होने की बात सामने आने का दावा किया गया।कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शासन द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, ऐसे में लंबे समय से गुड़-चना नहीं मिलने से हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने संबंधित विभाग से मामले की जांच कर लंबित खाद्य सामग्री का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने की मांग की।ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजय करन ने कहा कि हितग्राहियों को उनके अधिकार की खाद्य सामग्री समय पर मिलनी चाहिए। यदि वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा अनियमितता हुई है तो इसकी जांच कर जिम्मेदारों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना से बीजापुर में 66 हजार से अधिक मरीजों का उपचार

बीजापुर । मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत बीजापुर जिले के तीनों नगरीय निकायों– बीजापुर, भैरमगढ़ और भोपालपटनम में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिले में संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट महीने में 24 दिन अलग-अलग वार्डों और मोहल्लों में पहुंचकर स्वास्थ्य शिविर आयोजित करती है। सीएमओ बंसी लाल नूरुटी से मिली जानकारी के अनुसार अब तक जिले में 1,255 स्वास्थ्य शिविर लगाए जा चुके हैं, जिनमें 66,639 मरीजों का उपचार किया गया। वहीं 27,388 लोगों के 39,215 प्रकार के स्वास्थ्य परीक्षण किए गए तथा 63,223 लोगों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गईं।योजना के तहत सोमवार और मंगलवार को भोपालपटनम, गुरुवार और शुक्रवार को भैरमगढ़ तथा शनिवार और रविवार को बीजापुर में शिविर लगाए जाते हैं। रविवार को बीजापुर के साप्ताहिक बाजार में विशेष कैंप लगाया जाता है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। इसके अलावा पुलिस कॉलोनी, छात्रावास, बालगृह और पुनर्वास केंद्रों में भी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

16 सितंबर को तहसील स्तर पर किसान आंदोलन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन

भारतीय किसान संघ बस्तर ने किसानों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की

जगदलपुर। भारतीय किसान संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्देशानुसार किसान हितैषी मांगों को लेकर 16 सितंबर 2026, बुधवार को प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इसके तहत भारतीय किसान संघ जिला बस्तर की सभी तहसीलों में तहसील स्तर पर आंदोलन एवं ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक तहसील में भारतीय किसान संघ की तहसील कार्यकारिणी द्वारा तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। संगठन ने किसान हित से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित इस आंदोलन में अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है।भारतीय किसान संघ जिला बस्तर के जिलाध्यक्ष नील कुमार बघेल ने जिले के सभी तहसील अध्यक्ष, तहसील मंत्री, कार्यकारिणी सदस्यों एवं ग्राम इकाई के कार्यकर्ताओं से अपने-अपने क्षेत्र के किसानों के साथ आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि तहसील प्रभारी एवं सह-प्रभारी के नेतृत्व में आयोजित होने वाले ज्ञापन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संगठन के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सक्रिय रूप से जुटें। संगठन ने अपने आह्वान में कहा है कि ÷जो किसान हित में काम करेगा, वही देश में राज करेगा।÷ आंदोलन को लेकर जिला बस्तर की तहसीलों में तैयारियां की जा रही हैं।

पोटा केबिनों में डीईओ का औचक निरीक्षण, 10 अनुदेशक गैरहाजिर

तीन आवासीय संस्थाओं में मिली लापरवाही, अंतिम नोटिस देकर मांगा जवाब; बच्चों से सीधे जाना पढ़ाई और सुविधाओं का हाल

बीजापुर। एकलव्य विद्यालय की घटना के बाद आवासीय संस्थाओं की निगरानी को लेकर सवालों के बीच जिला शिक्षा अधिकारी राजेश पांडे ने उसूर ब्लॉक के पोटाकेबिन विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। मुरकीनार, दुगईगुड़ा, तिम्मापुर, बासागुड़ा और सारकेगुड़ा की संस्थाओं में पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं की पड़ताल की। इस दौरान तीन संस्थाओं में कुल 10 अनुदेशक अनुपस्थित मिले। डीईओ ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी को अंतिम नोटिस जारी किया है। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक ड्यूटी पर मौजूद मिले। डीईओ ने बच्चों से सीधे बातचीत कर पढ़ाई, भोजन, स्वास्थ्य और रहने की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। दुगईगुड़ा में कुछ बच्चों के बीमार होने की जानकारी पर उन्हें तत्काल स्वास्थ्य जांच कराने और दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।तिम्मापुर में शौचालय और परिसर की स्वच्छता सुधारने पर जोर दिया गया। वहीं बासागुड़ा में नियमित कक्षाओं के साथ सेतु पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों से पढ़ाई की प्रगति पूछी गई।

अधीक्षकों को परिसर में रहने की हिदायत-डीईओ ने अधीक्षकों को परिसर में मौजूद रहकर बच्चों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पढ़ाई में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने को कहा गया। अवकाश के दिनों में भी बच्चों को खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण में सामने आया

5 आवासीय संस्थाओं का निरीक्षण 3 संस्थाओं में 10 अनुदेशक अनुपस्थित सभी को अंतिम नोटिस बच्चों से सीधे लिया फीडबैकस्वास्थ्य और स्वच्छता सुधारने के निर्देश

मोपकी में तीज मिलन समारोह में शामिल हुए विधायक साव, त्योहार की खुशियाँ बांटीं और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की

बलौदा बाजार। ग्राम मोपकी में छत्तीसगढ़ का पारंपरिक और लोक संस्कृति से सराबोर तीज मिलन समारोह अत्यंत हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस गरिमामयी कार्यक्रम में विधायक इन्द्र साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ग्रामवासियों के साथ मिलकर त्योहार की खुशियाँ बांटीं और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। संबोधित करते हुए विधायक इन्द्र साव ने तीजा-पोरा त्योहार के सांस्कृतिक महत्व और इससे जुड़ी अटूट आस्था पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पोरा और तीजा का त्योहार छत्तीसगढ़ की माटी की महक, कृषि परंपरा और मातृशक्ति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह पर्व हमारे अन्नदाताओं और कृषि संस्कृति से जुड़ा है। यह त्योहार हमारी माताओं-बहनों के त्याग, तपस्या और अखंड सौभाग्य की कामना का प्रतीक है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति में बेटियाँ इस अवसर पर अपने मायके आती हैं, जहाँ उनका पारंपरिक रूप से आदर-सत्कार किया जाता है। यह त्योहार परिवारों के बीच आपसी प्रेम और सामाजिक समरसता को मजबूत करता है। इस पावन अवसर पर विधायक इंद्र साव ने आदिवासी समाज की वर्षों पुरानी और बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का विधि-विधान से भूमिपूजन किया। भूमिपूजन के बाद उन्होंने कहा कि यह भवन केवल एक संरचना नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, बैठकों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। समाज के विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं का होना बेहद जरूरी है और वे क्षेत्र के हर वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं। समाज के नागरिकों ने सामुदायिक भवन की सौगात मिलने पर विधायक इंद्र साव का आभार व्यक्त किया। तीज मिलन समारोह के दौरान भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कलाकारों ने छत्तीसगढ़ी लोक गीतों तथा पारंपरिक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं, जिससे पूरा माहौल उत्सव के रंग में सराबोर हो गया। कार्यक्रम का संचालन श्रीकांत मरकाम अध्यक्ष आदिवासी युवा प्रभाद ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अमर सिंह मंडावी जिला पंचायत सदस्य, जितू ठाकुर विधायक प्रतिनिधि, विशिष्ट अतिथि सरपंच अहिल्या कामता ध्रुव, उप सरपंच गीता श्यामरतन निषाद, जनपद सदस्य अगेश्वर ध्रुव, पुसउ मरकाम, मंडल अध्यक्ष कोमल साहू, देवसिंग ध्रुव, मोहन जगत, फिरंता ध्रुव, लीलाराम मरकाम संरक्षक, चैनू जगत सचिव सहित समाज के प्रमुख पदाधिकारी ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

लवन-सरखोर रोड में जगह जगह जानलेवा गड्ढे, राहगीर हो रहे है परेशान

बलौदा बाजार । लवन से सरखोर मार्ग की दूरी 6.15 किमी है। इस रोड को पांच साल पहले भाटापारा के ठेकेदार प्रमोद कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाई गई थी। इस रोड के लिए 125.05 लाख स्वीकृति मिली थी। इस सड़क को गुणवत्ता युक्त नहीं बनाने की वजह से समय से पहले ही सड़क पर जगह-जगह जानलेवा गड्ढे बन गए थे, रोड का डामर उखड़कर गड्ढों में तब्दील हो रहा है जो कि दुर्घटना को दावत देने के कगार पर पहुंच गए है। समय रहते इनकी मरम्मत नहीं कराई गई तो समस्या और अधिक विकराल हो सकती है। वाहन चालक गड्ढों की वजह से नियंत्रण खोकर दुर्घटना का शिकार हो रहे है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रोड को गुणवत्ताविहीन बनाया गया है जगह जगह से डामर निकल गए है जो खतरनाक गड्ढे में बदल रहे है, जिसकी वजह से स्थानीय राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ज्यादा अधिक गड्ढे की वजह से ही लोग गिरकर चोटिल भी हो रहे है। कम समय में ही यह रोड मरम्मत की कगार पर पहुंच गया है, और मरम्मत का समय आने पर भी विभाग द्वारा मरम्मत नहीं कराई जा रहीं है। यह रोड आम लोगों को आवाजाही के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग सरखोर, पंडरिया, जोंधरा होते हुए बिलासपुर जिले को जोड़ती है, इस वजह से इस मार्ग पर दोपहिया वाहनों का आना-जाना दिन भर होता रहता है। दोपहिया वाहन चालक रात में गड्ढों को भांप नहीं पाने की वजह से गिरकर दुर्घटना का भी शिकार हो रहे है। वहीं, ठेकेदार व विभाग द्वारा 12 टन से अधिक वजनी वाहनों प्रवेश निषेध का बोर्ड तो लगाया गया है, लेकिन वाहन चालक प्रवेश निषेध बोर्ड को दरकिनार कर भारी वाहनों को चलाते है, इस वजह से भी रोड खराब हो रहे है। भारी वाहनों की वजह से भी लवन, सरखोर मार्ग की हालत समय से पहले दम तोड़ रही है। मार्ग में जगह-जगह पर गड्ढे बन चूके है। इस रोड का संधारण कार्य करीब डेढ़ से दो दशक बीत जाने के बाद हुआ है। उस पर भी भारी वाहनों का दबाव बढ़ने से रोड जर्जर स्थिति में निर्मित हो रही है। राहगीरों को आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थनीय ग्रामीणों के द्वारा रोड़ मरम्मत की मांग गई है।

संक्षिप्त समाचार

राइस मिल एसोसिएशन ने रेडक्रॉस सोसायटी को दिए 5 लाख रुपए

बिलासपुर। जरूरतमंदों की सहायता और मानवीय सेवा के कार्यों में सहयोग के उद्देश्य से राइस मिल एसोसिएशन, बिलासपुर द्वारा जिला रेडक्रॉस सोसायटी को 5 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान की गई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर एवं रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल से आज मंथन सभाकक्ष में मुलाकात कर सहयोग राशि का चेक सौंपा। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने राइस मिल एसोसिएशन द्वारा जनहित और मानवीय सेवा के कार्यों में दिए गए इस सहयोग के लिए पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों की सहभागिता महत्वपूर्ण है। रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से प्राप्त सहयोग का उपयोग जरूरतमंद लोगों की सहायता एवं मानवीय सेवा के कार्यों में किया जाएगा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भविष्य में भी सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर खाद्य नियंत्रक श्री अमृत कुजूर, राइस मिल एसोसिएशन के महामंत्री शिवशंकर अग्रवाल सहित आदित्य अग्रवाल, सुनील, अनिकेत, राजेश, श्रीतेश, तेजस उपस्थित थे।

जिले में 20 चिन्हांकित स्थानों पर खुलेंगे आधार पंजीयन केंद्र बिल्हा, कोटा, तखतपुर और मस्तूरी जनपद क्षेत्रों में केंद्र संचालन के लिए 30 सितंबर तक आवेदन

बिलासपुर। जिले के चिन्हांकित शासकीय स्थानों पर आधार पंजीयन केंद्रों का संचालन किया जाना है। इसके लिए जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी बिलासपुर द्वारा आधार केंद्र संचालकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 16 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक कार्यालयीन समय में बंद लिफाफे में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जारी सूचना के अनुसार जिले में कुल 20 आधार किट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें जनपद पंचायत बिल्हा क्षेत्र में 3, कोटा में 8, तखतपुर में 3 तथा मस्तूरी में 6 आधार केंद्र शामिल हैं। आधार केंद्र संचालक के लिए प्रमुख पात्रताएं निर्धारित की गई हैं। आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा 2 वर्षीय आईटीआई या 3 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 1 जुलाई 2026 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना आवश्यक है तथा न्यूनतम एमएस ऑफिस/डिग्री-डिप्लोमा संबंधी वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा यू आई डी ए आई के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार एनएसइआईटीवी से वैध आधार सुपरवाइजर/ऑपरेटर प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। एनरोलमेंट एजेंसी कोड 2084 एवं 4082 से आधार सुपरवाइजर/ऑपरेटर परीक्षा प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे। आवेदन कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी बिलासपुर के नाम से कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। चयन प्रक्रिया एवं कार्य अनुमति का अंतिम निर्णय जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है।

आईटीआई कोनी में प्लेसमेंट कैंप 16 सितम्बर को

बिलासपुर। आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी द्वारा 16 सितम्बर 2026 को सवेरे 10 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में सुजुकी मोटर गुजरात द्वारा अपनी आवश्यकता अनुरूप प्रशिक्षित युवाओं का चयन किया जाएगा। कैंप में पेंटर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, प्लंबर, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एवं टूल एंड डाई मेकर व्यवसाय से वर्ष 2026 में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों सहित रोजगार के इच्छुक पात्र अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। अभ्यर्थियों को अपने साथ बायोडाटा रिज्यूमे, आईटीआई अंकसूची एवं प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां लाना अनिवार्य है। संस्था प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षणार्थियों से प्लेसमेंट कैंप में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कैंप का लाभ उठाने की अपील की गई है।

अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

कलेक्टर अग्रवाल ने जनदर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं

बिलासपुर। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने उनसे मिलकर निजी एवं सामुदायिक शिकायत संबंधी आवेदन दिया। उन्होंने अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मस्तुरी तहसील के ग्राम इटवा निवासी रामेश्वर यादव ने बताया कि उनकी पैतृक कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में 9 सदस्यों के नाम पर दर्ज है। जिसमें मेरे नाम से एग्रीटेक नहीं हो पा रहा है। इसके कारण वे धान बेच नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर से संबंधित भूमि पर अपने नाम से एग्रीटेक की कार्यवाही कराने का आग्रह किया। कलेक्टर ने तहसीलदार मस्तुरी को जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। रतनपुर तहसील के ग्राम सीस निवासी रामभाऊ डिक्सेना ने अधिक बारिश के कारण मकान गिरने से हुई क्षति का उल्लेख करते हुए आर्थिक सहायता की मांग की। आवेदन में बताया गया कि लगातार बारिश के कारण उनका कच्चा मकान गिर गया, जिससे परिवार के सामने रहने की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने शासन से नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया। कलेक्टर ने उनका आवेदन तहसीलदार रतनपुर को सौंपा। ग्राम गोड़ाडीह के संतनु कुमार कुर्रे सहित ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि गोड़ाडीह में स्थित जिंदल पावर एंड स्टील कंपनी में स्थानीय लोगों द्वारा रोजगार की मांग को लेकर पूर्व में धरना-प्रदर्शन किया गया था। कंपनी की ओर से स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक स्थानीय बेरोजगार युवाओं को अपेक्षित रोजगार नहीं मिला है। उन्होंने कंपनी पर उचित कार्यवाही कर स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने की मांग की। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को मामले को सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। जनपद पंचायत तखतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरीकला के ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की मजदूरी के भुगतान में अनियमितता की शिकायत करते हुए जांच की मांग की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में नाली निर्माण कार्य कराया गया, जिसमें मजदूरी का भुगतान सरपंच द्वारा स्वयं एवं अन्य परिचित के नाम पर किया गया। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर द्वारा इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ को आवश्यक कार्यवाही करने कहा गया। कोटा क्षेत्र के आवेदक भारत सिंह ने कलेक्टर के समक्ष सर्वेयर कार्य का भुगतान लंबित होने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदक ने बताया कि सर्वेयर के रूप में कार्य करने के बाद उनकी करीब 18,730 रुपये की भुगतान राशि लंबित है। भुगतान के लिए आवश्यक दस्तावेज तहसील कार्यालय में जमा किए जाने के बावजूद राशि प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने लंबित भुगतान शीघ्र दिलाने की मांग की। कलेक्टर ने आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारी को उनका आवेदन सौंपा। मस्तुरी तहसील क्षेत्र के सतीश पाल सहित अन्य ग्रामीण किसानों ने बताया कि ग्राम पंचायत जयरामनगर खैरा बस्ती निवासी कमल सोनी और दिलहरण यादव द्वारा चूना पत्थर की खदान में राखड़ (फ्लाई ऐश) की पटाई की गई थी। इस राखड़ का उचित रख-रखाव न करने और उसे खुला छोड़ देने के कारण इस वर्ष जुलाई और अगस्त माह की भारी बारिश में यह बहकर किसानों के खेतों में जा घुसा।

रेलवे की कॉपर केबल चोरी करने वाले दिल्ली के संगठित गिरोह का पर्दाफाश....

- 10 चोरों एवं 7 रिसीवरों सहित कुल 17 आरोपी गिरफ्तार, 4 स्कूटर जब्त
- चोरी की रेलवे संपत्ति दिल्ली के चांदनी चौक स्थित कबाड़ मंडी में बेचने की बात आई सामने

बिलासपुर। बुढ़ार, सिंहपुर, छादा एवं शहडोल क्षेत्र में रेलवे की कॉपर केबल चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, बिलासपुर के मार्गदर्शन में RPF की विशेष टीम एवं RPF पोस्ट अनूपपुर ने संयुक्त कार्रवाई कर एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई में 10 आरोपियों एवं चोरी की रेलवे संपत्ति खरीदने वाले 7 रिसीवरों सहित कुल 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी में प्रयुक्त 4 स्कूटर भी जब्त किए गए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी दिल्ली से आकर अनूपपुर क्षेत्र में किराए के मकानों में रह रहे थे तथा स्कूटर से घूमकर रेलवे की कॉपर केबल एवं अन्य तांबे की सामग्री की रेकी कर चोरी करते थे। चोरी की सामग्री को दिल्ली के चांदनी चौक स्थित कबाड़ मंडी में बेचने की बात पूछताछ में सामने आई है। RPF द्वारा प्रभावित रेलखंडों में लगातार निगरानी, पेट्रोलिंग, एम्बुश एवं स्थानीय मुखबिर तंत्र के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में दो आरोपियों को ट्रेन से भागते समय उमरिया से तथा एक आरोपी को गाजियाबाद स्थित उसके निवास से पकड़ा गया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई कॉपर केबल एवं अन्य तांबे की रेलवे सामग्री बरामद की गई है। मामले में आगे की जांच जारी है तथा गिरोह से जुड़े अन्य व्यक्तियों एवं चोरी की संपत्ति के खरीदारों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।

रायगढ़ स्टेशन व ब्रजराजनगर-रायगढ़-चांपा बिलासपुर-भाटापारा सेक्शन में चला 48 घंटे का महा टिकट चेकिंग अभियान

- बिना टिकट, अनियमित टिकट यात्रा व बिना बुक लगेज के 733 मामलों से 6.70 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल द्वारा यात्रियों को सुगम व सुविधाजनक रेल यात्रा उपलब्ध कराने, रेलवे नियमों के पालन सुनिश्चित करने तथा बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से निरंतर टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 12 एवं 13 सितम्बर 2026 को वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन में मंडल के रायगढ़ स्टेशन व ब्रजराजनगर-रायगढ़-चांपा-बिलासपुर-भाटापारा सेक्शन में 48 घंटे का महा टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें वाणिज्य निरीक्षक, मुख्य टिकट निरीक्षक एवं टीटीई स्टाफ शामिल थे। इस अभियान के दौरान रायगढ़ स्टेशन व ब्रजराजनगर-रायगढ़-चांपा-बिलासपुर-भाटापारा सेक्शन से गुजरने वाली 47 ट्रेनों की सघन जांच कर कुल 733 मामलों से 6,70,155 रुपये का जुर्माना वसूला गया। जिसमें बिना टिकट यात्रा के 601 मामलों से 06 लाख 10 हजार 880 रुपये, अनियमित टिकट के 73 मामले से 52 हजार 925 रुपये तथा बिना बुक लगेज के 59 मामलों 06 हजार 350 रूपये का जुर्माना शामिल है 7 रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व उचित यात्रा टिकट अवश्य लें तथा स्टेशन परिसर में प्रवेश हेतु प्लेटफॉर्म टिकट खरीदें।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा की..

- व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक होंगे विभिन्न आयोजन
- पुलिस मैदान में 17 सितंबर को सवा लाख दीए जलाए जाएंगे

बिलासपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज वीसी के जरिए बिलासपुर में 'सेवा संकल्प अभियान' की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस अभियान को जनभागीदारी के साथ व्यापक स्वरूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रम केवल जिला मुख्यालय तक सीमित न रहें, बल्कि जनपद, तहसील, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर तक प्रभावी रूप से आयोजित किए जाएं। जिला स्तरीय मुख्य समारोह बिलासपुर के पुलिस मैदान में होगा, जहां 17 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री मोदी की जन्म दिन पर 1.25 लाख दीए जलाए जाएंगे। मंथन की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी और महापौर पूजा विधानी उपस्थित थीं। विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री सुशांत शुक्ला, क्रेडा अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी और हर्षिता पाण्डे भी बैठक में ऑनलाइन मोड से शामिल हुई। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं, स्वसहायता समूहों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने विभागवार तैयारियों की जानकारी लेते हुए सभी कार्यक्रमों का समयबद्ध क्रियान्वयन और नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। अभियान के तहत 'आशीर्वाद का दीया', 'सेवा की कहानी', 'नमो सेवा गाथा', 'आंगन का उत्सव', 'सेवा ज्योति कलश यात्रा', 'सेवा मेरा योगदान' 'जल जन सेवा संकल्प' और 'सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार' सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विद्यालयों में चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिताएं, आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण जागरूकता कार्यक्रम तथा स्वच्छता एवं जनसेवा से जुड़ी गतिविधियां भी होंगी। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने जिले में अभियान की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि व्यापक जनभागीदारी के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित कर दिनवार एवं तिथिवार कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना से गंगा साहू बनीं आत्मनिर्भर

परिवार की आर्थिक स्थिति को दे रहीं मजबूती

बिलासपुर। शहर की रहने वाली श्रीमती गंगा साहू के जीवन में छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित "दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना" ने सकारात्मक बदलाव लाया है। योजना का लाभ मिलने से अब वे न केवल आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। योजना का लाभ मिलने से पहले श्रीमती गंगा साहू गृहणी थीं। उनका अधिकांश समय बच्चों की देखरेख और घर-गृहस्थी के कार्यों में व्यतीत होता था। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच स्वयं की आय का कोई साधन नहीं था। ऐसे में श्रम विभाग की दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना उनके लिए नई उम्मीद लेकर आई। शासन से प्राप्त सहायता के माध्यम से उन्हें ई-रिक्शा उपलब्ध हुआ। ई-रिक्शा संचालन से अब वे नियमित रूप से रोजगार प्राप्त कर अपनी आमदनी अर्जित कर रही हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है और वे आर्थिक रूप से सशक्त होकर परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सहयोग दे रही हैं। श्रीमती गंगा साहू बताती हैं कि पहले वे केवल घरेलू कार्यों तक सीमित थीं, लेकिन शासन की योजना से उन्हें रोजगार का अवसर मिला। आज वे अपने पैरों पर खड़ी होकर परिवार के खर्चों में हाथ बंटा रही हैं। उनके लिए यह योजना केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि "आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ जीवन जीने का माध्यम" बनी है। दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। श्रीमती गंगा साहू ने शासन द्वारा मिली इस सहायता के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया और अन्य महिलाओं को भी योजना का लाभ उठाने हेतु प्रेरित कर रही है।

महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने रायपुर स्टेशन पर चल रहे मेजर स्टेशन रिडेवलपमेंट एवं पुनर्विकास कार्यों का किया निरीक्षण

- निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर उच्च गुणवत्ता, यात्री सुविधा एवं संरक्षा को प्राथमिकता देने के दिए दिशा-निर्देश

बिलासपुर। श्री तरुण प्रकाश, महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने आज 14 सितम्बर 2026 को रायपुर स्टेशन का निरीक्षण कर स्टेशन पर चल रहे मेजर स्टेशन रिडेवलपमेंट एवं पुनर्विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश ने रायपुर स्टेशन पर चल रहे विभिन्न विकास एवं पुनर्विकास कार्यों का विस्तृत अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों से कार्यों की वर्तमान प्रगति, निर्धारित समय-सीमा एवं आगामी कार्ययोजना की जानकारी ली। उन्होंने स्टेशन पुनर्विकास से संबंधित ले-आउट प्लान का अवलोकन करते हुए वास्तविक स्थिति से परखा एवं अधिकारियों को सभी कार्यों को निर्धारित मानकों एवं उच्च गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर महाप्रबंधक ने कहा कि स्टेशन पुनर्विकास कार्यों के दौरान यात्रियों की सुविधा, संरक्षा एवं सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। निर्माण कार्यों के कारण यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा कार्यस्थल पर उचित संरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश भी दिए। महाप्रबंधक ने रायपुर स्टेशन के विभिन्न प्लेटफार्मों, फुट ओवर ब्रिज सहित अन्य महत्वपूर्ण यात्री क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेते हुए स्वच्छता, बेहतर यात्री आवागमन तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को यात्रियों को संरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास करने के निर्देश दिए। महाप्रबंधक ने स्टेशन पर मुख्य प्रवेश द्वार गेट नंबर 02 पर निर्माणाधीन कार्य के लिए घेराबंदी से लेकर स्टेशन के गुढ़ियारी छोर पर चल रहे प्रगतिशील कार्यों का अवलोकन करते हुए निर्माण की गुणवत्ता एवं कार्य की गति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। रायपुर स्टेशन का पुनर्विकास कार्य यात्रियों को आधुनिक एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुनर्विकास के उपरांत स्टेशन पर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर आवागमन व्यवस्था, सुविधाजनक प्रवेश एवं निकास तथा अधिक सुव्यवस्थित यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश ने अधिकारियों को स्टेशन पुनर्विकास के सभी कार्यों में आपसी समन्वय बनाए रखते हुए गुणवत्ता, समयबद्धता एवं संरक्षा के निर्धारित मानकों का पूर्णत: पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रायपुर के सभागार में महाप्रबंधक द्वारा रायपुर मंडल के रेल परिचालन एवं विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में रेल परिचालन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, अधोसंरचना विकास कार्यों के दौरान निर्बाध एवं सुचारू रेल परिचालन पर जोर देते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

किचन में 3 बर्नर गैस चूल्हा रखना शुभ है या अशुभ?

घर में किचन को काफी अहम जगह माना जाता है। वास्तु शास्त्र में भी रसोई से जुड़ी कई बातों का जिक्र मिलता है। गैस चूल्हा किचन की सबसे जरूरी चीजों में से एक है और इसे किस दिशा में रखा जाए, इसे लेकर भी कई वास्तु नियम बताए जाते हैं। ऐसे में अगर आपके घर में 3 बर्नर वाला गैस चूल्हा है या आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं, तो जान लें क्या तीन बर्नर गैस चूल्हा लेना शुभ माना जाता है या नहीं।

क्या 3 बर्नर वाला चूल्हा अशुभ होता है?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार सिर्फ चूल्हे में तीन बर्नर होने को अशुभ नहीं माना जाता। चूल्हे का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है और उसे किचन में किस जगह रखा गया है, इन बातों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए अगर आपकी जरूरत के हिसाब से 3 बर्नर वाला गैस स्टोव सही है, तो इसे रखने में कोई खास वास्तु दोष नहीं माना जाता।

किस दिशा में रखना माना जाता है सही?

वास्तु के अनुसार किचन में गैस चूल्हे के लिए दक्षिण-पूर्व दिशा को सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसे अग्नि तत्व की दिशा कहा जाता है। अगर किचन का लेआउट ऐसा हो कि चूल्हा इस दिशा में रखा जा सके, तो इसे वास्तु के लिहाज से अच्छा माना जाता है।चूल्हा रखते समय यह भी ध्यान रखें कि खाना बनाते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर रहे। वास्तु मान्यताओं में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खाना बनाना शुभ माना जाता है।

चूल्हे और सिंक के बीच रखें दूरी

किचन में गैस चूल्हे के ठीक पास सिंक रखना वास्तु के हिसाब से सही नहीं माना जाता, क्योंकि चूल्हा अग्नि और सिंक जल तत्व से जुड़ा माना जाता है। अगर किचन छोटा है और ज्यादा विकल्प नहीं हैं, तो सिंक और गैस स्टोव के बीच कोई सुरक्षित स्पेस या काउंटर एरिया रखा जा सकता है। इससे रोजमर्रा के काम में भी आसानी रहती है।

बलराम जयंती पर भगवान बलराम की पूजा

बलराम जयंती 2026 भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। भगवान बलराम को बल, धर्म, सत्य, पराक्रम और कर्तव्य के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उन्हें बलदेव, बलभद्र और हलधर जैसे नामों से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक परंपराओं में बलराम जी का विशेष स्थान है। उनके हाथ में रहने वाला हल और मूसल उनके प्रमुख प्रतीक माने जाते हैं। बलराम जयंती के दिन भक्त भगवान बलराम की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि तथा शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं।

बलराम जयंती 2026 कब है?

बलराम जयंती 2026 बुधवार, 16 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी। यह पर्व भाद्रपद शुक्ल षष्ठी से जुड़ा हुआ है। 2026 में षष्ठी तिथि 16 सितंबर को सुबह लगभग 8:59 बजे शुरू होकर 17 सितंबर को सुबह लगभग 10:47 बजे समाप्त होगी। पूजा का स्थानीय मुहूर्त शहर और पंचांग के अनुसार अलग हो सकता है। बलराम जयंती को कई स्थानों पर बलदेव छठ और कुछ क्षेत्रों में बलभद्र जयंती के नाम से भी जाना जाता है।

भगवान बलराम कौन हैं?

भगवान बलराम, भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई माने जाते हैं। धार्मिक परंपरा में उन्हें बल, शक्ति और धर्म के स्वरूप के रूप में देखा जाता है। उनके प्रमुख नाम हैं: बलराम, बलदेव, बलभद्र, हलधर, हलायुध, संकर्षण। भगवान बलराम का प्रमुख अस्त्र हल माना जाता है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। कुछ वैष्णव परंपराओं में बलराम जी को भगवान विष्णु से संबंधित दिव्य स्वरूप माना जाता है, जबकि अन्य परंपराओं में उन्हें भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य विस्तार तथा अनंत शेष से संबंधित माना जाता है।

बलराम जयंती का महत्व

बलराम जयंती केवल भगवान बलराम के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह शक्ति, अनुशासन, धर्म और कर्तव्य की भावना को याद करने का अवसर भी माना जाता है। इस दिन भक्त भगवान बलराम से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में: शारीरिक और मानसिक शक्ति बनी रहे। परिवार में सुख और शांति रहे। व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखे। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। नकारात्मकता और भय से मुक्ति मिले। जीवन में अनुशासन और संयम बना रहे।

बलराम जयंती की कथा

धार्मिक परंपराओं के अनुसार, भगवान बलराम का जन्म वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में हुआ था। कंस को भविष्यवाणी से भय था कि देवकी का आठवां पुत्र उसका अंत करेगा।भगवान विष्णु की दिव्य व्यवस्था के अनुसार बलराम जी के गर्भ का स्थानांतरण देवकी से रोहिणी के गर्भ में हुआ। इसी कारण उन्हें संकर्षण नाम से भी जाना जाता है।बाद में रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ और उनका पालन-पोषण गोकुल तथा व्रज की भूमि में हुआ।भगवान बलराम बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी माने जाते थे। वे श्रीकृष्ण के साथ अनेक लीलाओं में सहभागी रहे।

भगवान बलराम और श्रीकृष्ण का संबंध

भगवान बलराम और श्रीकृष्ण का संबंध हिंदू धार्मिक कथाओं में अत्यंत विशेष माना जाता है। बलराम जी श्रीकृष्ण के बड़े भाई थे और कई प्रसंगों में उन्होंने श्रीकृष्ण का साथ दिया। व्रज की लीलाओं में दोनों भाइयों का प्रेम, मित्रता और परस्पर सहयोग देखने को मिलता है।बलराम जी को श्रीकृष्ण के संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में भी देखा जाता है। बलराम जयंती पूजा विधि बलराम जयंती के दिन भक्त अपनी क्षमता और पारिवारिक परंपरा के अनुसार भगवान बलराम की पूजा कर सकते हैं।

1. सुबह स्नान करें

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करें।

2. पूजा स्थल तैयार करें

भगवान बलराम जी की तस्वीर या प्रतिमा को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। यदि उपलब्ध हो तो श्रीकृष्ण और भगवान बलराम दोनों की पूजा साथ में की जा सकती है।

3. संकल्प लें

हाथ में जल लेकर भगवान बलराम की पूजा और व्रत का संकल्प लें। मन में अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रार्थना करें।

4. भगवान बलराम को जल अर्पित करें

भगवान बलराम जी को जल अर्पित करें और पुष्प चढ़ाएं। चंदन, अक्षत और धूप-दीप भी अर्पित किए जा सकते हैं।

5. हलधर स्वरूप का स्मरण करें

भगवान बलराम को हलधर कहा जाता है। पूजा के दौरान उनके हलधारी स्वरूप का ध्यान करें और जीवन में शक्ति, धैर्य तथा सही कर्म की प्रार्थना करें।

कंधे से नहीं सरकेगा ब्लाउज, अपनाएं ये 5 आसान हैक्स

शादी, पार्टी या किसी कैजुअल मौके पर साड़ी या लहंगे के साथ खूबसूरत ब्लाउज पहनना हर किसी को पसंद होता है। लेकिन कई बार ब्लाउज कंधे से बार बार नीचे खिसकने लगता है। ऐसे में बार बार उसे ठीक करना पड़ता है और पूरा लुक भी खराब हो सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो कुछ आसान फैशन हैक्स की मदद से इस परेशानी को दूर किया जा सकता है।

बैक डोरी से ब्लाउज को दें सपोर्ट

अगर ब्लाउज का बैक नेक काफी डीप है और कंधे बार बार नीचे आ रहे हैं, तो पीछे डोरी लगवाना अच्छा विकल्प हो सकता है। डोरी में मैचिंग लटकन या टैसल भी लगवा सकती हैं। इससे ब्लाउज का ऊपरी हिस्सा अपनी जगह पर बना रहता है और साथ ही ब्लाउज का लुक भी और खूबसूरत नजर आता है।

सिलिकॉन शोल्डर पैड्स का करें इस्तेमाल

कई बार कंधे थोड़े ढलान वाले होने की वजह से भी ब्लाउज नीचे खिसकने लगता है। ऐसे में सिलिकॉन शोल्डर पैड्स मदद कर सकते हैं। इन्हें ब्रा स्ट्रैप के नीचे रखा जा सकता है। इससे कंधे पर बेहतर ग्रिप मिलती है और ब्लाउज को सहारा मिलता है। यह तरीका खासतौर पर उन ब्लाउज में काम आ सकता है जो कंधे से आसानी से फिसल जाते हैं।

ब्रा स्ट्रैप के लिए लूप लगवाएं

ब्लाउज के कंधे के अंदर की तरफ एक छोटा सा रिबन या कपड़े का लूप लगवाया जा सकता है। इसमें एक छोटा स्नैप बटन लगवा लें। ब्लाउज पहनने के बाद लूप को ब्रा स्ट्रैप के चारों ओर लगाकर बटन बंद कर दें। इससे ब्लाउज की शोल्डर लाइन अपनी जगह पर बनी रहती है और कंधे से नीचे खिसकने की परेशानी कम हो जाती है।

डबल साइडेड फैशन टेप आएगा काम

अगर ब्लाउज में लूप नहीं लगा है और आपको तुरंत कोई आसान उपाय चाहिए, तो डबल साइडेड फैशन टेप इस्तेमाल कर सकती हैं। ब्लाउज के अंदर कंधे वाले हिस्से पर थोड़ा सा टेप लगाएं और उसे त्वचा या ब्रा स्ट्रैप के साथ चिपका दें। इससे कपड़ा अपनी जगह पर टिका रहता है। टेप इस्तेमाल करने से पहले यह जरूर देख लें कि वह त्वचा पर इस्तेमाल के लिए सुरक्षित हो।

चेहरे की डेड स्किन हटाने के उपाय

चेहरे पर डेड स्किन जमा होने से स्किन बेजान और रूखी नजर आ सकती है। कई बार चेहरा साफ करने के बाद भी त्वचा पर एक अलग तरह की परत महसूस होती है। पटना की ब्यूटिशियन रानी के अनुसार, डेड स्किन को हटाने के लिए चेहरे पर बहुत ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं होती।

हल्की एक्सफोलिएशन और सही मॉइस्चराइजिंग से स्किन को साफ और मुलायम रखने में मदद मिल सकती है। ऐसे में स्किन केयर रूटीन में हल्की एक्सफोलिएशन और मॉइस्चराइजिंग को शामिल किया जा सकता है। इसके लिए हर बार महंगे प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। घर में मौजूद कुछ आसान चीजों से भी सिंपल DIY केयर की जा सकती है।

● शहद से करें स्किन को नरम

शहद स्किन को मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है। अगर चेहरे पर रूखापन ज्यादा महसूस होता है, तो थोड़े से शहद को चेहरे पर पतली परत में लगाया जा सकता है। एक चम्मच शहद लें। साफ चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं। करीब 10 मिनट तक लगा रहने दें। फिर सामान्य पानी से चेहरा धो लें। इसके बाद हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं

दही से करें हल्की DIY केयर

दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो त्वचा की सतह पर मौजूद डेड स्किन को धीरे-धीरे हटाने में मदद करता है। इसके लिए सादा और बिना फ्लेवर वाला दही इस्तेमाल करें। एक चम्मच सादा दही लें। इसे साफ चेहरे पर लगाएं। 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। पानी से अच्छी तरह चेहरा साफ कर लें। बाद में मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं।

● ओट्स से बनाएं जेंटल फेस पैक

अगर आपको स्क्रब करने की आदत है, तो चेहरे पर मोटे कणों वाले स्क्रब की जगह बारीक पिसे ओट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओट्स स्किन को बहुत ज्यादा रगड़े बिना साफ करने में मदद करता है। एक चम्मच बारीक पिसे ओट्स लें। इसमें थोड़ा सा पानी या सादा दही मिलाएं। पेस्ट को चेहरे पर लगाएं करीब 5 से 10 मिनट बाद पानी से धो लें। चेहरे को तौलिए से रगड़ने की बजाय हल्के हाथों से सुखाएं

● एलोवेरा जेल से दें ठंडक

डेड स्किन हटाने के बाद त्वचा को शांत और हाइड्रेट रखना भी जरूरी है। इसके लिए एलोवेरा जेल यूज करें। अगर आपके पास एलोवेरा जेल है, तो उसकी थोड़ी मात्रा चेहरे पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर धो लें।

आज का राशिफल

मेष राशि - आज का दिन आपके लिए काफी सार्थक रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और किसी महत्वपूर्ण काम में सकारात्मक परिणाम मिलने से आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। किसी बेहद करीबी मित्र की मदद से कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है। परिवार की ओर से कोई अच्छी खबर आपका मन प्रसन्न कर देगी, वहीं जीवनसाथी के साथ बिताया समय रिश्ते में मिठास बढ़ाएगा।

वृषभ राशि - आज परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और पहले से बनाई गई योजनाओं में से कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। विद्यार्थियों के करियर में ऐसा बदलाव आ सकता है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। सोशल मीडिया या ऑनलाइन क्षेत्र से जुड़े लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिससे आगे चलकर लाभ मिलेगा। कारोबार में कुछ लोग आपका साथ देंगे और दोस्तों के साथ भी अच्छा समय बीतेगा।

मिथुन राशि - आज आप अपने लक्ष्य को लेकर काफी गंभीर नजर आएंगे और उन्हें हासिल करने के लिए नई योजना बना सकते हैं। अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है और अप्रत्याशित धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। किसी अपने की मदद से वह काम भी आसान हो जाएगा, जिसे लेकर आप कुछ समय से चिंतित थे।

कर्क राशि - आज का दिन मिला-जुला रहेगा, लेकिन समझदारी से काम लेने पर आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह या सहायता किसी महत्वपूर्ण काम में काफी उपयोगी साबित होगी। परिवार के साथ मनोरंजन का कार्यक्रम बन सकता है और घर में अच्छा माहौल रहेगा। हालांकि पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें और अनावश्यक आर्थिक जोखिम लेने से बचें। बीती हुई बातों को बार-बार सोचकर अपना वर्तमान खराब न करें।

सिंह राशि - आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी सफलता काफी हद तक आपके व्यवहार और निर्णय लेने के तरीके पर निर्भर करेगी। अपनी सोच और व्यवहार में संतुलन बनाए रखें और किसी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और जीवनसाथी के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। आज बड़े और जल्दबाजी वाले फैसले लेने से बचना ही समझदारी होगी।

कन्या राशि - आज का दिन खुशियों और सकारात्मक घटनाओं से भरा रहेगा। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा और टीमवर्क से काम आसानी से पूरे होंगे। अचानक किसी नए स्रोत से धन लाभ हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति संतुलित होगी। शाम तक किसी समारोह या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात पुरानी यादें ताजा कर देगी और मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल है और कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है।

तुला राशि- आज कामकाज की व्यस्तता बनी रहेगी और ऑफिस में आपको किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से रखने का अवसर मिल सकता है। आपकी बात का आसपास के लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी, लेकिन परिवार से जुड़े कुछ मामलों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। दोस्तों के साथ घूमने-फिरने का कार्यक्रम बन सकता है और परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा,

वृश्चिक राशि - आपको परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की जरूरत होगी। कोई महत्वपूर्ण काम उम्मीद से थोड़ा अधिक समय ले सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। नौकरी या व्यवसाय में आपकी रणनीति उपयोगी साबित होगी। आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जोखिम लेने से बचें। परिवार के किसी सदस्य से भावनात्मक सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में साथी के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करें। दिन के अंत में मानसिक सुकून महसूस होगा।

धनु राशि- आज का दिन आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होंगे और आप थोड़ी-सी अतिरिक्त मेहनत करके अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आने के संकेत हैं। कारोबार के लिहाज से भी दिन लाभकारी रहेगा। किसी भी काम को जल्दबाजी के बजाय धैर्य और समझदारी से पूरा करने की कोशिश करें।

मकर राशि - आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। परिवार से जुड़े किसी काम के कारण थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह संभाल लेंगे। ऑफिस में काम की गति बढ़ेगी और महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होने की संभावना है। भाई-बहन के साथ किसी विषय पर विचार-विमर्श होगा और किसी नए काम की योजना भी बन सकती है। बच्चों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

कुंभ राशि- आज आपके सामने कामकाज से जुड़ा कोई बड़ा अवसर आ सकता है और सही समय पर उठाया गया कदम आपको अच्छा लाभ दिला सकता है। किस्मत का साथ मिलने से मुश्किल काम भी आसान होते नजर आएंगे। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और परिवार में आपसी विश्वास तथा प्रेम बढ़ेगा। अचानक धन लाभ का कोई अवसर मिल सकता है। आपके काम से प्रभावित होकर लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं।

मीन राशि- आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा और किसी खास काम में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। भाई-बहन के साथ रिश्तों में सुधार आएगा और आपसी समझ बढ़ेगी। जीवनसाथी आपकी बातों और विचारों से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे दाम्पत्य संबंधों में सकारात्मकता आएगी। व्यापार के मामलों में दिन अच्छा रहेगा और सामाजिक कार्यों में भी सफलता मिलने के संकेत हैं। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा।

माउथवॉश के इस्तेमाल से पहले जानें 7 जरूरी बातें

ब्रशिंग और फ्लॉसिंग के साथ माउथवॉश को डेली रूटीन में शामिल करने की सलाह डेंटिस्ट देते हैं। लेकिन इसके ज्यादा या फिर केमिकल से भरपूर माउथवॉश के इस्तेमाल से ड्राई माउथ या फिर टिशूज के सेंसिटिव हो जाने की समस्या भी हो सकती है। इस आर्टिकल में हम माउथवॉश से जुड़े ऐसे 7 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपको बेहतर रिजल्ट पाने में मदद कर सकते हैं।

डेंटिस्ट भी नहीं हैं एकमत

कई डेंटिस्ट ब्रशिंग और फ्लॉसिंग के साथ माउथवॉश को भी जरूरी मानते हैं। इससे सहमत एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रश और फ्लॉस मुंह के हर कोने में नहीं पहुंच पाते। जबकि माउथवॉश आपकी इस मुश्किल को चुटकियों में हल कर देता है। वहीं, कुछ डेंटिस्ट इसके इस्तेमाल को उतनी अहमियत नहीं देते।

ब्रशिंग को रिप्लेस नहीं करता

भले ही यह आपके मुंह के हाइजीन को मेंटेन रखता है, लेकिन यह ब्रशिंग का विकल्प नहीं है। माउथवॉश से कुल्ला भर कर लेना कीटाणुओं और प्लाक को हटाने के लिए काफी नहीं। लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और माउथवॉश को ही कम्प्लीट केयर मान लेते हैं।

सेंसेशन का मतलब असरदार होना नहीं

अगर माउथवॉश इस्तेमाल करते ही मुंह के अंदर जलन हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपना काम बेहतर कर रहा है। माउथवॉश से होने वाली जलन अल्कोहल या उसमें एड किए गए फ्लेवर की वजह से हो सकता है।

गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं

कुछ माउथवॉश में एंटीमाइक्रोबायल एजेंट होते हैं जोकि बैक्टीरिया को मारते हैं, लेकिन यह गुड या बैड बैक्टीरिया के बीच अंतर नहीं कर पाते। जबकि गुड बैक्टीरिया आपके मुंह की सेहत के लिए जरूरी माने जाते हैं।

लेबल जरूर पढ़ें

कोई भी माउथवॉश लेने से पहले यह चेक कर लें कि उसमें अल्कोहल और सोडियम लॉरेल सल्फेट या एसएलएस तो नहीं। ज्यादातर माउथ केयर प्रोडक्ट्स में ये दो तत्व पाए जाते हैं। ऐसा माउथवॉश देखें, जिसका अल्कलाइन पीएच हो और यह जितना ज्यादा होगा, मुंह की सेहत के लिए उतना ही बेहतर है।

ब्लडप्रेशर पर असर

मुंह में ऐसे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं जो भोजन से मिलने वाले नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देते हैं। इससे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में भी मदद मिलती है। वहीं लगातार ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले एंटीमाइक्रोबायल माउथवॉश इस्तेमाल करने से यह संतुलन बिगड़ सकता है। हालांकि, इस असंतुलन को सीधे माउथवॉश के इस्तेमाल से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, अभी इस दिशा में रिसर्च जारी है।

कौन सी दाल खाना आपके लिए सबसे फायदेमंद

भारतीय खानपान में दाल की अपनी खास जगह है। शाकाहारी लोगों के लिए खासतौर से ये प्रोटीन का सबसे सस्ता और पॉपुलर सोर्स है। साथ ही इसे डाइट में शामिल करना भी आसान होता है। अब दाल कई तरह की होती हैं, अरहर दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल; लेकिन क्या सभी दाल सेम होती हैं? आमतौर पर हम कोई भी दाल बनाकर खा लेते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि हमारे लिए कौन सी दाल सबसे बेहतर है। इस बारे में एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए डॉ पूजा रेड्डी विस्तार में बताती है। डॉक्टर कहती हैं कि हमारे देश में हर दूसरे देश से ज्यादा दाल खाई जाती हैं, लेकिन हमें कोई नहीं बताता कि कौन सी दाल कब खानी है। उन्होंने एक कंप्लीट दाल गाइड शेयर की हैं, जिसे जानना काफी फायदेमंद हो सकता है।

पाचन से जुड़ी प्रॉब्लम हो तो खाएं ये दाल

अगर आपको पाचन से जुड़ी कोई समस्या हो रही है, तो आपके लिए पीली मूंग दाल सबसे बेहतर है। ये धुली हुई और छिलका उतरी हुई होती है, साथ ही गट के लिए ब्रेकडाउन में सबसे आसान होती है। अगर आपको खाने के बाद भारीपन महसूस होता है तो ये दाल आपके लिए बेस्ट है।

इस दाल में है सबसे ज्यादा प्रोटीन

अगर आप प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए दाल खा रहे हैं, तो मसूर दाल आपके लिए बेस्ट है। डॉक्टर कहती हैं कि 100 ग्राम मसूर दाल में आपको आराम से 24 ग्राम के करीब प्रोटीन मिल जाता है और फटाफट पक भी जाती है। अगर आपको खाने के बाद भारीपन महसूस होता है, तो भी मसूर दाल अच्छा ऑप्शन हो सकती है।

डायबिटीज वालों के लिए बेस्ट है ये दाल

अगर आपको डायबिटीज या इन्सुलिन रेसिस्टेंट की समस्या है तो चना दाल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, जो दुनियाभर के सबसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स में से एक है। सिंपल शब्दों में कहें तो चना दाल खाने से शुगर लेवल ना के बराबर ही बढ़ता है।

ज्यादा फाइबर चाहिए? ये वाली दाल खाएं

अगर आपको फाइबर रिच दाल खानी है, तो साबुत हरी मूंग दाल एक अच्छा ऑप्शन है। डॉक्टर कहती हैं कि ये फाइबर से भरपूर भी है, साथ ही उड़द दाल की तरह पेट पर भारी भी नहीं पड़ती।

मिट्टी के गणेश बनाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

भिलाई। स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती महाविद्यालय, हुडको में विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण-अनुकूल उत्सवों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमा निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम कला संकाय, वाणिज्य विभाग एवं माइक्रोबायोलॉजी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। कार्यशाला में बीएड तृतीय सेमेस्टर के डिकेश चंद्राकर एवं बीए तृतीय सेमेस्टर के फरहद कामरान खान ने विद्यार्थियों को प्राकृतिक सामग्री से गणेश प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण दिया।

कार्यशाला में विद्यार्थियों ने प्राकृतिक मिट्टी और जैव-अवक्रमणीय सामग्री से गणेश प्रतिमाएं तैयार कीं। खास बात यह रही कि प्रतिमाओं में बीज भी डाले गए, ताकि विसर्जन के बाद मिट्टी में मौजूद बीजों से पौधे उग सकें और हरियाली का संदेश प्रसारित हो। विद्यार्थियों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर हल्दी, चावल, धान, फूल-पत्तियां, विभिन्न दालें, सिंदूर और चंदन जैसी प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग कर प्रतिमाओं को आकर्षक स्वरूप दिया।

कार्यशाला के माध्यम से विद्यार्थियों ने संदेश दिया कि आस्था और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर भी त्योहारों को सुंदर एवं सार्थक तरीके से मनाया जा सकता है। विद्यार्थियों ने जलस्रोतों के संरक्षण और स्वच्छ एवं हरित वातावरण के प्रति जागरूकता फैलाते हुए पर्यावरण-अनुकूल गणेश उत्सव मनाने का संकल्प लिया।

श्री शंकराचार्य शैक्षणिक परिसर हुडको के निदेशक डॉ. दीपक शर्मा एवं डॉ. मोनिशा शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। आस्था तभी सार्थक है, जब उसमें प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना भी जुड़ी हो। उन्होंने विद्यार्थियों से इस संदेश को परिवार और समाज तक पहुंचाने का आह्वान किया।

महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. हंसा शुक्ला ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इसमें विद्यार्थियों की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां विद्यार्थियों में रचनात्मकता, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करती हैं। उन्होंने प्राकृतिक एवं पर्यावरण-अनुकूल सामग्री अपनाने की अपील की।

कार्यक्रम का संयोजन कला संकाय की विभागाध्यक्ष डॉ. सुनीता वर्मा, माइक्रोबायोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. शमा ए. बेग एवं वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉ. शर्मिला शामल ने किया। प्रबंधन विभागाध्यक्ष श्रीमती खुशबू पाठक ने भी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉ. मंजू कनौजिया, सहायक प्राध्यापक अमरजीत, इंद्राणी दास एवं ज्योति मिश्रा का विशेष सहयोग रहा। कार्यशाला में विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। कार्यक्रम का संदेश रहा– ÷श्रद्धा वही, उत्सव वही–बस प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी नई÷ और ÷मिट्टी का गणेश बनाएं, पर्यावरण को बचाएं।÷

भिलाई टाउनशिप के आवासों में मवेशी पालन पर रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

भिलाई। भिलाई टाउनशिप के आवासों एवं आवासीय परिसरों में मवेशी पालन की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद टाउनशिप के विभिन्न आवासों में मवेशी पालन किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। मवेशियों के कारण आसपास के क्षेत्रों में गंदगी एवं दुर्गंध फैलने के साथ-साथ आवागमन में भी परेशानी होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएँ विभाग के अनुसार, टाउनशिप में पाले जा रहे मवेशी अधिकांश समय खुले में घूमते रहते हैं। इनके सड़कों पर घूमने, दौड़ने अथवा आपस में लड़ने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है और ऐसी घटनाओं के कारण लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। नगर सेवाएँ विभाग ने टाउनशिप के ऐसे आवासधारियों से अपील की है कि वे अपने आवासों अथवा आवासीय परिसरों में मवेशी पालन की गतिविधियों को तत्काल बंद करें। टाउनशिप क्षेत्र में स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं सड़क सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवासधारियों से निर्धारित नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मवेशी के कारण टाउनशिप क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है अथवा मवेशियों से उत्पन्न गंदगी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, तो संबंधित चिन्हित मवेशी पालक आवासधारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

चकबंदी लेखपाल पर फरियादी को कमरे में बंद कर पीटने और मोबाइल छीनने का आरोप

गाजीपुर। सदर चकबंदी कार्यालय में फरियाद लेकर पहुंचे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को लेखपाल द्वारा कमरे में बंद कर मारपीट करने और मोबाइल छीनने का मामला सामने आया है। ग्राम सकरा निवासी अशोक कन्नौजिया ने लेखपाल सूरज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस और जिलाधिकारी को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत के अनुसार, अशोक कन्नौजिया मंगलवार की सुबह करीब साढ़े दस बजे राजस्व परिषद प्रयागराज के आदेश का अनुपालन कराने के संबंध में सदर चकबंदी कार्यालय पहुंचे थे। वहां उन्होंने गांव के लेखपाल सूरज से आदेश पर अमल होने की जानकारी मांगी। आरोप है कि इस दौरान लेखपाल ने उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए गाली-गलौज की।

अशोक का आरोप है कि आदेश का अनुपालन कराने के लिए लेखपाल ने उनसे 40 हजार रुपये लिए थे। काम नहीं होने पर जब उन्होंने रकम वापस मांगी तो लेखपाल ने चपरासी एजाज से दरवाजा बंद करने को कहा। शिकायतकर्ता के मुताबिक, कमरे में मौजूद सुरेश कुमार बिंद को बाहर भेजने के बाद दरवाजा बंद कर दिया गया और उन्हें डराया-धमकाया गया।

आरोप है कि इसी दौरान सहायक चकबंदी अधिकारी सदर कमरे में पहुंचे और बीच-बचाव किया। उनके जाने के बाद लेखपाल ने अशोक की जेब में रखा मोबाइल जबरन छीन लिया तथा मारपीट करते हुए धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया।

शिकायत में लेखपाल सूरज पर पूर्व में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए जाने और करीब छह माह बाद जमानत पर जेल से बाहर आने का भी आरोप लगाया गया है। इसके अलावा फर्जी कुटुंब रजिस्टर की नकल और जीवित व्यक्ति का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में हेराफेरी के संबंध में कोतवाली थाने में एफआईआर संख्या 0637/2025 दर्ज होने का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

ओआरएस की आड़ में शराब का खेल, 1074 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

असम से समस्तीपुर जा रही थी खेप, ट्रक में 1100 पेटी हाइड्रेशन ड्रिंक के बीच छिपाकर रखी थी शराब

पूर्णिया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तस्कर पुलिस की नजरों से बचने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं। पूर्णिया में अब ओआरएस यानी हाइड्रेशन ड्रिंक की आड़ में विदेशी शराब की बड़ी खेप ले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक से 1074.6 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक असम से शराब की खेप लेकर पूर्णिया के रास्ते समस्तीपुर जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जीरो माइल शीशाबाड़ी मस्जिद के पास घेराबंदी कर ट्रक को रोक लिया। ट्रक में चालक सहित तीन लोग सवार थे। पूछताछ में आरोपियों ने ट्रक में एप्पल हाइड्रेशन ड्रिंक होने की जानकारी दी। संदेह होने पर पुलिस ने ट्रक की विधिवत तलाशी ली, जिसमें हाइड्रेशन ड्रिंक की आड़ में छिपाकर रखी गई विदेशी शराब का खुलासा हुआ। तलाशी के दौरान ट्रक से विभिन्न ब्रांड की 110 पेटी विदेशी शराब बरामद हुई। इसकी कुल मात्रा 1074.6 लीटर बताई गई है। इसके अलावा ट्रक में 1100 पेटी एप्पल हाइड्रेशन ड्रिंक भी मिली, जिसकी कुल मात्रा करीब 17,820 लीटर है।

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बरामद शराब समस्तीपुर निवासी नीतीश कुमार की होने की बात बताई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ट्रक चालक सह मालिक भूषण राय, प्रमोद राय और नीलेश कुमार के रूप में हुई है। तीनों समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र के चकजलाल गांव के निवासी बताए गए हैं।

पुलिस अब शराब तस्करी के इस नेटवर्क की पूरी कड़ी खंगालने में जुटी है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि शराब की खेप कहां से मंगाई गई थी और इसे समस्तीपुर में किसके पास पहुंचाया जाना था। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है।

प्रेम प्रकाश पांडे की पहल रंग लाई : सार्वजनिक पंडालों से हटाया गया 3.50 रुपये प्रति वर्गफीट कर

गणेश-दुर्गा उत्सव समितियों को बड़ी राहत, प्रदेशभर में समितियां करमुक्त

भिलाई। सार्वजनिक गणेश एवं दुर्गा उत्सव समितियों को राज्य शासन ने बड़ी राहत दी है। सार्वजनिक पंडालों पर लगाया जाने वाला 3.50 रुपये प्रति वर्गफीट का कर हटा दिया गया है। इससे प्रदेशभर में धार्मिक आयोजनों के लिए लगाए जाने वाले सार्वजनिक पंडाल करमुक्त हो गए हैं। शासन के इस फैसले से उत्सव समितियों में खुशी की लहर है।

विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ने उठाया था मुद्दा– पंडालों पर कर लगाए जाने से उत्सव समितियों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा था। इसे लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में विरोध के स्वर भी उठने लगे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने इस मुद्दे को शासन के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया।

पांडे ने शासन से आग्रह किया था कि धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के लिए सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाने वाले पंडालों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाना चाहिए। उनकी पहल के बाद शासन ने 3.50 रुपये प्रति वर्गफीट कर हटाने का निर्णय लिया।

आयोजन समितियों को मिलेगी आर्थिक राहत– कर हटने से अब गणेश एवं दुर्गा उत्सव समितियों को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में पंडाल का कर जमा करने का अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। इससे बचने वाली राशि का उपयोग धार्मिक आयोजनों, पंडालों की साज-सज्जा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य व्यवस्थाओं में किया जा सकेगा।

राजेंद्र सिंह अरोरा ने जताया आभार– नगर निगम भिलाई के पूर्व सभापति राजेंद्र सिंह अरोरा ने सार्वजनिक उत्सव समितियों को मिली इस राहत के लिए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे एवं राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कर हटने से धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों से जुड़ी समितियों को आर्थिक राहत मिलेगी और उत्सवों का आयोजन बेहतर ढंग से किया जा सकेगा।

पर्यूषण पर्व का प्रथम दिवस सहित 5 पर्व-त्योहारों पर मांस-मटन एवं पशुवध गृह रहेंगे पूर्णतः बंद

नगर निगम दुर्ग ने जारी किया आदेश, उल्लंघन पर होगी वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई,

दुर्ग। नगर पालिक निगम, दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग) द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित समस्त पशुवध गृह (स्लाटर हाउस), जीव हत्या तथा मांस-मटन एवं मछली विक्रय केन्द्रों को निर्धारित पर्व एवं त्यौहारों के अवसर पर पूर्णतः बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है। नगर निगम द्वारा निर्धारित बंद दिवसों 15 सितंबर, मंगलवार को पर्यूषण पर्व का प्रथम दिवस, 22 सितंबर, मंगलवार को डोल ग्यारस, 25 सितंबर, शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी एवं पर्यूषण पर्व का अंतिम दिवस, 26 सितंबर, शनिवार को पर्यूषण पर्व में संवत्सरी व उत्तम क्षमा तथा 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को महात्मा गांधी जन्मदिवस शामिल हैं।उक्त सभी तिथियों को नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्रांतर्गत समस्त पशुवध गृह, जीव हत्या तथा मांस, मटन एवं मछली विक्रय केन्द्र अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे।नगर निगम ने सभी संबंधित व्यवसायियों एवं विक्रय केन्द्र संचालकों से शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक, जब्ती एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जमीन सौदा विवाद में संगीता शाह की औपचारिक गिरफ्तारी, अग्रिम जमानत के चलते रिहाई

हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सुपेला थाने पहुंचीं, पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी की

भिलाई। ग्राम कोहका की जमीन के सौदे से जुड़े धोखाधड़ी के आरोपों के मामले में सिम्प्लेक्स कास्टिंग लिमिटेड की डायरेक्टर संगीता केतन शाह 14 सितंबर को सुपेला थाने पहुंचीं। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद उन्होंने पुलिस के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराई। पुलिस ने प्रकरण में उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की कार्रवाई पूरी की और अग्रिम जमानत के आदेश के तहत आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया ।

इस मामले में सुपेला पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बाद 8 मई 2026 को संगीता केतन शाह और उनके पति केतन मूलचंद शाह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत अपराध दर्ज किया था। एफआईआर में लगाए गए आरोपों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। आरोप अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं और आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

50 लाख में जमीन का सौदा करने का आरोप– शिकायतकर्ता सुनील कुमार सोमेन के अनुसार, 13 मार्च 2023 को ग्राम कोहका स्थित करीब 0.10 हेक्टेयर जमीन का सौदा संगीता शाह के साथ 50 लाख रुपये में तय हुआ था। शिकायत के

मुताबिक, इसके एवज में 10 लाख रुपये एडवांस दिए गए। आरोप है कि बाद में जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई। शिकायतकर्ता का यह भी दावा है कि बाद में जमीन से संबंधित किराए और लीज विवाद की जानकारी सामने आई, जिसकी जानकारी सौदे के समय नहीं दी गई थी।

शिकायत में इसी जमीन के दस्तावेजों के आधार पर एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड से करीब 4.50 करोड़ रुपये का ऋण लिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। इन आरोपों की पुष्टि या खंडन जांच के निष्कर्ष और न्यायिक प्रक्रिया से होना है।

न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर– शिकायतकर्ता के अनुसार, पुलिस स्तर पर कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश के बाद सुपेला थाने में एफआईआर दर्ज की गई।

हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत– मामले में दुर्ग जिला न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद संगीता शाह और केतन शाह ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने बैंक रिकॉर्ड के आधार पर शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपये वापस किए जाने का तथ्य रखा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को अग्रिम जमानत प्रदान की।

अग्रिम जमानत का अर्थ यह है कि आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में निर्धारित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है। यह आरोपों से दोषमुक्ति या मामले के समाप्त होने का आदेश नहीं होता। मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी रहती है।

थाने में पूरी हुई गिरफ्तारी की औपचारिकता– हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में संगीता शाह 14 सितंबर को सुपेला थाने पहुंचीं। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की और अग्रिम जमानत के आदेश के अनुसार उन्हें रिहा कर दिया। इसलिए इसे ÷अग्रिम जमानत के बावजूद गिरफ्तारी÷ के बजाय ÷अग्रिम जमानत के आदेश के अनुपालन में औपचारिक गिरफ्तारी और तत्पश्चात रिहाई÷ कहना अधिक कानूनी रूप से सटीक होगा।

थाने पहुंचने के दौरान पत्रकारों ने संगीता शाह से मामले को लेकर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की। उनके अधिवक्ता की ओर से भी तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

सोशल मीडिया पर संगीता शाह और उनके पति की विभिन्न नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल होने की बात भी सामने आई है। संगीता शाह पूर्व विधानसभा चुनाव में वैशाली नगर सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि, इन तस्वीरों का जमीन विवाद और दर्ज आपराधिक प्रकरण से कोई कानूनी संबंध है, ऐसा पुलिस या न्यायालय की ओर से नहीं कहा गया है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। डाक पंजीयन क्रमांक- सीजी/दुर्ग/लोकतंत्र प्रहरी/2026-28, Email : loktantraprahrinews@gmail.com